पेज 07 में...
हैदराबाद को
लखनऊ ने रौंदा

साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 06 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 08 में...
कांग्रेस बोली-बस्तर के हर
गांव को 1 करोड़ दे सरकार

वर्ष : 02 अंक : 05 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com
पेज 12 जनगणना 2026-27 : मकानों की गिनती 16 से

नया वित्त वर्ष, अब बरसेंगी लक्ष्मी

ज्ञान, गति और अब संकल्प की परीक्षा की वार्षिक घड़ी

राज्य के 2026-2027 के नए वित्त वर्ष का हुआ आगाज़

2025-26 में 1,65,000 लाख करोड़ रुपए एवं 2026-27 में बजट 1,72,000 लाख करोड़ रुपए

महिलाओं, युवाओं, बेटियों पर बरसेगी सुशासन की अमृत धारा

प्रमुख संवाददाता/विकास यादव
मोबाईल नंबर 9425528000

राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारी निवेश की तैयारी में है साय सरकार। नए वित्त वर्ष के प्रारम्भ होते ही बजट का आकार ऐसा है कि सभी वर्गों का विकास इस सुशासन में ही हो जायेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा राज इतना लंबा रहा है कि भविष्य में विकास और उन्नति के बाद विकसित राज्यों की फेहरिस्त में अगर शामिल हुआ तो इसका क्रेडिट भी भाजपा को ही जायेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह देश के विकास के लिए कांग्रेस को मिली मियाद और किये गए कार्यों की तुलना आज संसद से लेकर राज्यों की विधानसभा में बहस का मुद्दा होती हैं।

विकसित भारत- विकसित छत्तीसगढ़ का वर्ष शुरू- साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए वित्त वर्ष के लिए स्वीकृत बजट के संबंध में कहा; "हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने में विश्वास रखती है। इन मिशनों से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को 'विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना का आधार स्तंभ बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अब पारंपरिक तरीकों के बजाय 'मिशन मोड' में काम कर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। सुशासन का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों तक इसका प्रभाव असरकारक रहे। बजट विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना पर आधारित है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने में विश्वास रखती है। पांच मुख्यमंत्री मिशन बनाए हैं। इससे प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार मिलेगी।

मुख्यमंत्री के विजन के मुख्य बिंदु

पांच मुख्यमंत्री मिशन

राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पांच विशेष 'मुख्यमंत्री मिशन' का गठन किया गया है। ये मिशन विशिष्ट लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने पर केंद्रित होंगे।

नई दिशा और धार

मुख्यमंत्री के अनुसार, यह बजट केवल वित्तीय आवंटन नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई दिशा और धार देने की कार्ययोजना है।

तेज रफ्तार विकास

शासन व्यवस्था में सुधार और योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई रफ्तार दी जाएगी।

संकल्प से सिद्धि

सरकार का लक्ष्य 2047 तक छत्तीसगढ़ को देश के सबसे अग्रणी और विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है।

समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प - चौधरी

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को विकसित छत्तीसगढ़ @2047 की नींव बताया। उन्होंने कहा कि सरकार 'ज्ञान' (GYAN) और 'गति' के बाद अब 'संकल्प' की रणनीति पर काम कर रही है। "यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि 2047 तक एक समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प है।"

विजन 2047: विकसित राज्य का लक्ष्य

अमृतकाल की कार्ययोजना: प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए 'छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट' तैयार किया गया है।

समावेशी विकास: बजट का मुख्य फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी शक्ति (GYAN) के उत्थान पर है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा

विकसित भारत जी रामजी योजना: मनरेगा से इतर ठोस संपत्तियों के निर्माण हेतु 4,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक प्रावधान।

कृषि सहायता: कृषक उन्नति योजना हेतु 10,000 करोड़ और बिजली सब्सिडी के लिए 5,500 करोड़ रुपये आवंटित।

कनेक्टिविटी: 'सीजी वायु योजना' के तहत बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में हवाई सेवा विस्तार और 36 प्रमुख सड़कों का दो-लेन चौड़ीकरण।

शिक्षा और युवा सशक्तिकरण

प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद: 'उड़ान', 'शिखर' और 'मंजिल' योजनाओं के जरिए युवाओं को आर्थिक सहायता।

एजुकेशन सिटी: अबूझमाड़ और जगरगुंडा में नई एजुकेशन सिटी की स्थापना।

औद्योगिक पार्क: युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क (250 करोड़ रुपये)।

बस्तर और सरगुजा का ध्यान

क्षेत्रीय विकास: बस्तर-सरगुजा प्राधिकरणों के लिए 150 करोड़ और स्थानीय प्रतिभाओं हेतु 'बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स' का आयोजन।

सुरक्षा और रोजगार: 1,500 बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन और नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी रणनीति।

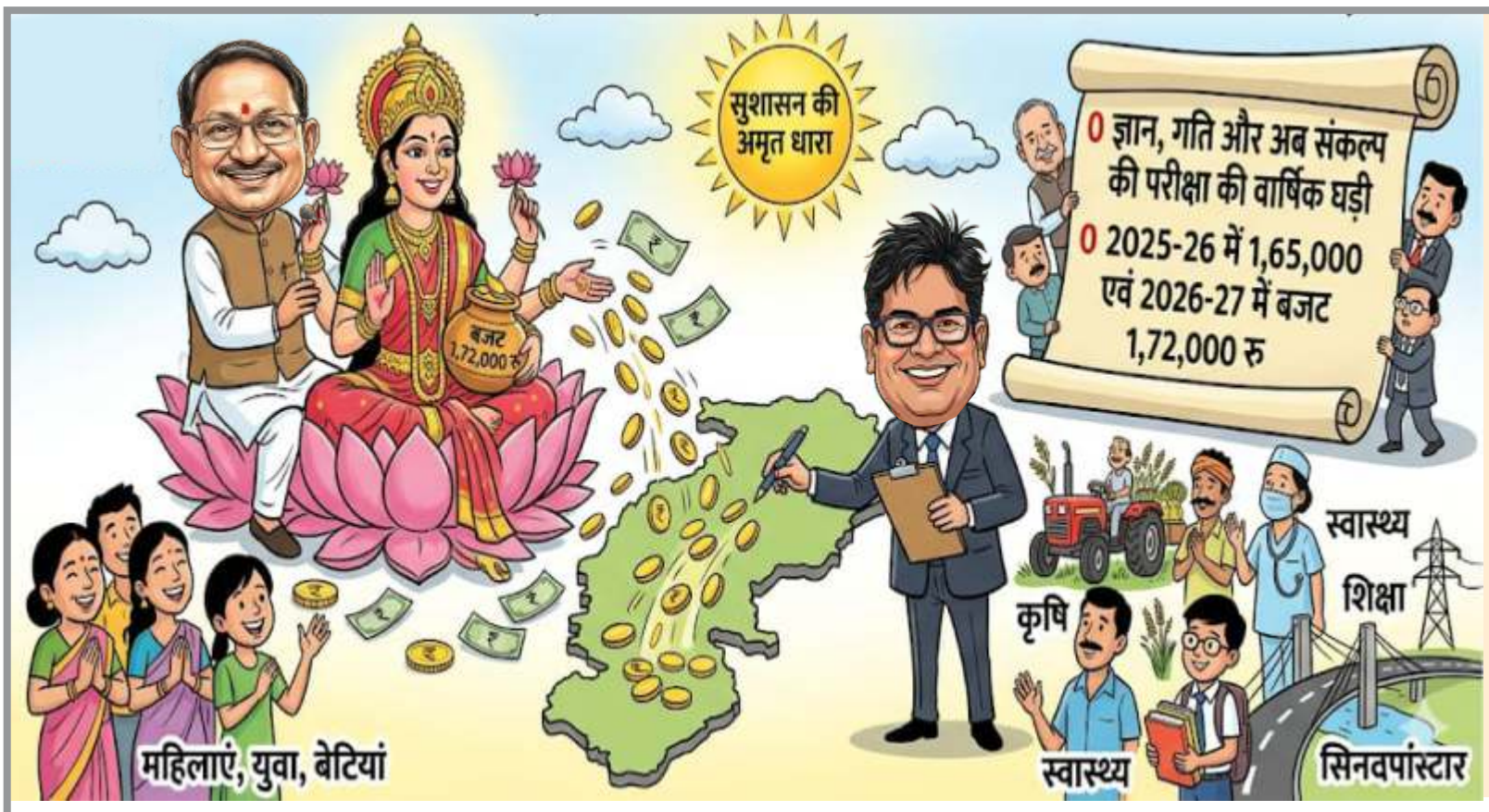

नए वित्त वर्ष से बहुरेंगे दिन

- **शिक्षा और कौशल:** स्कूल शिक्षा हेतु ₹22,360 करोड़, उच्च शिक्षा में युवा-केंद्रित पहलों के लिए ₹1,097 करोड़।
- **कृषि और ग्रामीण विकास:** कृषि क्षेत्र को ₹13,507 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए ₹16,560 करोड़।
- **महिला एवं बाल विकास:** महिला एवं बाल विकास के लिए ₹11,000 करोड़ और 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बेटियों के लिए योजना।
- **स्वास्थ्य:** शासकीय कर्मचारियों के लिए ₹100 करोड़ के प्रावधान के साथ कैशलेस चिकित्सा योजना।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर:** लोक निर्माण विभाग के लिए ₹9,451 करोड़ और ऊर्जा विभाग को ₹9,015 करोड़ आवंटित।
- **गरीब कल्याण:** मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु ₹5,000 करोड़।
- **विशेष प्रावधान:** बस्तर फाइटर्स के लिए 1,500 नए पदों का सृजन।

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश के लिए 2026-2027 के नए वित्त वर्ष का आगाज़ हो गया है। बजट का ग़ज़र भी बज उठा है और विभागवार अलॉटमेंट का फरमान भी जारी हो गया है। अगर सुशासन का यह बजट पूरी ईमानदारी से विभाग जनहित में सदुपयोग करे तो भांजे राम के ननिहाल को रामराज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। शांत, सौम्य और संस्कारी मुख्यमंत्री हैं तो प्रशासन की नब्ज से पूरी तरह वाकिफ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं जो चाहें तो इसी कार्यकाल में छत्तीसगढ़ और यहां के लोगों के दिन बहुरा सकते हैं। कसर तो विभागाध्यक्षों की तरह से रहती है; योजना, प्रस्ताव और नीतियों को जनहित में जरूरतमंदों तक बेरोकटोक पहुँचाने के बदले आधे रास्ते इन नीतियों का गला घोंट देते हैं। सहीं मॉनिटरिंग से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ही अपने संकल्पी और गति वाले बजट को मूर्तरूप दे सकते हैं। बिना किसी शक-ओ-शुबा के इसकी तिमाही और छःमाही के बाद की बजट राशि वे जिन विभागों को दें तो इसके साथ ही विभागाध्यक्षों समेत मंत्रियों को भी सख्त ताक़ीद करें। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.72 लाख करोड़ का 'संकल्प' बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से लगभग 4.2% अधिक है।

नई योजनाएं

Viksit Bharat G RAM G योजना

Viksit Bharat G RAM G योजना के लिए 4,000 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में 125 दिवस का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण एवं जन-सुविधाएँ भी विकसित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना

आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है, जिससे नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में बुनियादी अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं, स्वच्छता इत्यादि में सुधार लाया जा सके।

मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना

द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में तीव्र गति वाली 2/4 लेन सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है।

स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना

स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देशय शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर केंद्रित है।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा

राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है।

CG ACE

प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक सहायता हेतु CG ACE Chhattisgarh Assistance for Competitive Exams योजना अंतर्गत 33 करोड़ का प्रावधान है। इसके 3 घटक उड़ान, शिखर एवं मंजिल के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रवेश तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
उड़ान NEET / JEE/CLAT प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
शिखर UPSC/CGPSC के लिए
मंजिल - रेलवे / बैंकिंग / SSC के लिए

CG VAYU

CG VAYU Chhattisgarh Viability Assistance for Yatri Udaan के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर से हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करना है।

रानी दुर्गावती योजना

परिवार में बालिका के जन्म पश्चात्, बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.50 लाख रूपये दिये जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना

आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए Rental आवासीय सुविधा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजनांतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

लखपति दीदी भ्रमण योजना

सरकार ने इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में प्रदेश की लखपति दीदीयों को, सफल महिला उद्यमियों की कार्य प्रणाली तथा उनके सफल व्यवसाय मॉडल का अध्ययन करने हेतु देश के अंदर आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के Exposure Visit के लिए लखपति दीदी भ्रमण योजना में 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लखपति दीदी बहनों को प्रदेश के शक्ति पीठों के दर्शन की भी व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में निरंतरता रखते हुए इस बजट में महिलाओं के नाम पर भूमि, भवन, अचल सम्पत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी।

मुख्यमंत्री आस्था पथ (शक्ति पीठ भ्रमण) योजना

धार्मिक पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से राज्य के 5 शक्तिपीठ कुदरगढ़, रतनपुर, चन्द्रपुर, डोंगरगढ़ तथा दंतेवाड़ा स्थित आस्था केन्द्रों के दर्शन हेतु आस्था पथ (शक्ति पीठ भ्रमण) योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• वर्ष 2026-27 का बजट आबंटन •

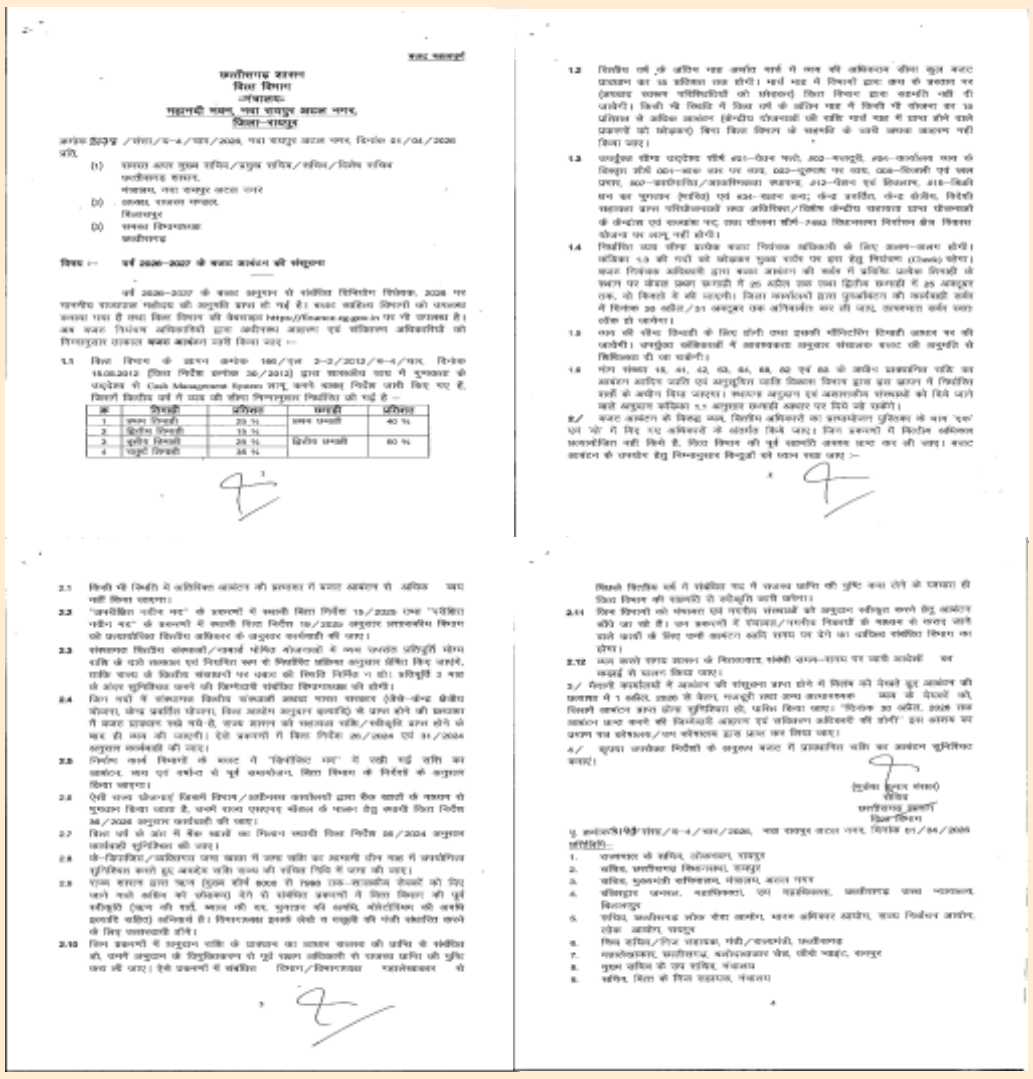

2025-26 में 1,65,000 लाख करोड़ रुपए एवं 2026-27 में बजट 1,72,000 लाख करोड़ रुपए

विभाग	2025-26	2026- 27	वृद्धि (%)
महिला एवं बाल विकास	8245	11000	+33%
उद्योग एवं व्यापार	1420	1600	+12.7%
उच्च शिक्षा	1615	1800	+11.5%
इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी	380	420	+10.5%
परिवहन	210	230	+9.5%
खेल एवं युवा कल्याण	168	180	+7.1%
जनसंपर्क	562	600	+6.8%
पशुपालन	745	780	+4.7%
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	9440	9600	+1.7%
लोक निर्माण विभाग	9501	9451	-1%
जल संसाधन	3800	3500	-7.89%

वर्ष बजट	प्रावधान	पूंजीगत व्यय का प्रावधान
2001-02	4,944	500
2011-12	30,726	5,076
2021-22	97,106	13,839
2023-24	1,30,458	15,418
2024-25	1,51,700	22,300
2025-26	1,65,000	26,341
2026-27	1,72,000	26,500

जीएसटी से बच रहे डेढ़ लाख व्यापारी

10 अप्रेल के बाद कच्चे का सौदा करने वालों को नोटिस

शहर सत्ता/रायपुर। जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी रोकने के लिए अब सख्ती बढ़ा दी है। विभाग के सर्वे में सामने आया है कि जितने व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग जीएसटी के दायरे में आते हैं, उनमें से बड़ी संख्या अब तक पंजीयन ही नहीं करवा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार, जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है और सेवा क्षेत्र में जिनकी आय 20 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार ऐसे पात्र लोगों की संख्या करीब 3.5 लाख होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में केवल लगभग 2 लाख लोगों ने ही जीएसटी का भुगतान किया है।

इस बड़े अंतर को देखते हुए विभाग ने अब कार्रवाई का प्लान तैयार किया है और 10 अप्रैल के बाद अपंजीकृत कारोबारियों को नोटिस भेजने की तैयारी है। विभाग ने बैंकों के साथ ही छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी से भी उन इलाकों की सूची मांगी गई है, जहां बिजली की खपत दोगुनी हो गई है। ऐसे सभी जगहों स्थित फैक्ट्रियों, उद्योगों या कारखानों की भी जांच की जाएगी। इनके टर्नओवर और कारोबार की पूरी जानकारी निकाली जाएगी। स्टेट जीएसटी ने अपनी शुरुआत जांच के दौरान पाया कि नॉन ब्रांडेड सामाग्री का कारोबार करने वाले पंजीयन नहीं करा रहे हैं। इनमें जूते, चप्पल, कपड़े, फर्नीचर, बर्तन, प्लास्टिक एसेसरीज जैसी सामाग्री का कारोबारी शामिल हैं। अफसरों के अनुसार ब्रांडेड कंपनियां जीएसटी भुगतान के साथ ही बाजार में कारोबार करती हैं। लेकिन नॉन ब्रांडेड और लोकल सामाग्री बनाते या बेचते हैं वे जीएसटी पंजीयन कराते ही नहीं है।

जीएसटी नंबर नहीं दिखाया तो जुर्माना

जीएसटी का पंजीयन कराने के बाद सभी कारोबारियों को दुकानों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों के बाहर उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। जो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 30 हजार का जुर्माना लगेगा। अभी कई बार जीएसटी विभाग के अफसर व्यापारियों को जानकारी चस्पा करने के लिए समय दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। अफसरों का कहना है कि बार-बार चेतावनी के बाद भी वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस वजह से अब जांच के दौरान सबसे पहले इसी बात की जांच की जाएगी व्यापारी ने जानकारी डिस्प्ले की है या नहीं? अभी 40 प्रतिशत व्यापारी जानकारी डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं।

कोयला-ट्रांसपोर्टिंग में सबसे ज्यादा धांधली

जीएसटी विभाग के अफसरों ने कोयला और ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वालों पर खास नजर रखनी शुरू कर दी है। अभी ज्यादा गड़बड़ी इस तरह के कारोबार में ही मिल रही है। दोनों सेक्टर के बड़े कारोबारी इस तरह का काम बिना बिल के सबसे ज्यादा कर रहे हैं। विभाग के सर्वे में यह आया कि छोटे कारोबारी जिनका टर्नओवर बड़ा है वे जीएसटी में पंजीयन नहीं करवा रहे हैं। बैंकों और बिजली कंपनी से इसकी जानकारी भी ली जा रही है। ऐसे लोगों के पास विभाग की टीम जाकर उन्हें जागरूक करेगी। इस साल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या हर हाल में बढ़ेगी।

रायपुर-उरकुरा-मांढर सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम

शहर सत्ता/रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में चल रहे काम की वजह से आज कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

14 ट्रेन प्रभावित, एक पैसेंजर समेत 9 मेमू पूरी तरह रद्द, 4 ट्रेनें आंशिक रूप से कैंसिल

रायपुर-उरकुरा-मांढर सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगाने का काम किया जा रहा है। जिस कारण कुछ ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी और कुछ आंशिक रूप से चलेंगी। 11 मेमू ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है। और 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द (बीच से चलेंगी) रहेंगी। यानी ये ट्रेन पूरी तरह बंद नहीं होगी, बल्कि अपने पूरे रूट का कुछ हिस्सा नहीं चलती। आसान भाषा में कहें तो ट्रेन कुछ स्टेशनों तक ही चलेगी। आगे का सफर रद्द रहेगा या फिर ट्रेन बीच के किसी स्टेशन से ही शुरू होगी, शुरुआती हिस्सा रद्द रहेगा।

68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू
68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू
68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू
68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू
58205 रायपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी पैसेंजर
68701 रायपुर-दुर्ग मेमू
68702 दुर्ग-रायपुर मेमू
68703 रायपुर-दुर्ग मेमू
68704 दुर्ग-रायपुर मेमू
6 अप्रैल 2026 को 58206 इतवारी-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।

रहेजा बिल्डर की साइट में हादसा, मजदूर जिंदा दफन

आठ फीट मिट्टी के नीचे दबा झारखंड का कारपेंटर

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर के कचना इलाके में निर्माणाधीन रहेजा प्रोजेक्ट साइट पर शनिवार की दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी धंसने से एक मजदूर जिंदा दफन हो गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र की है। हादसे के बाद साइट पर हड़कंप मच गया और काम बंद कर दिया गया। मृतक का नाम गुड्डू रवि बताया जा रहा है। मृतक झारखंड के गडवा जिले के निवासी है। संतोष कुमार नाम के ठेकेदार के साथ काम करने के लिए रहेजा बिल्डर के परिसर में आया हुआ था। पुलिस अधिकारियों और चश्मदीदों के अनुसार क्लब हाउस निर्माण के दौरान ये हादसा हुआ है। कारपेंटर गुड्डू रवि शाम चार बजे अपने साथियों के साथ काम कर रहा था। गुड्डू गड्ढे में नीचे खड़ा था। गुड्डू का साथी पानी पीने के लिए बढा, इस दौरान मिट्टी का ढेर गुड्डू पर गिर गया और वो जिंदा दफन हो गया। साथी कर्मचारी जब तक बाहर निकालते, तब तक वो मर चुका था।

एक महीने पहले आया था रायपुर

मृतक के शव को लेने के लिए रायपुर पहुंचे उसके भाई पुलेंदर कुमार ने बताया, कि एक महीने पर गुड्डू रवि काम करने के लिए रायपुर आया हुआ था। शनिवार की दोपहर को उसकी बात उससे हुई थी। शाम चार बजे जब वो दुकान में था, तो गुड्डू के फोन में कॉल आया। कॉल करने वाले शख्स ने बताया, कि भाई की तबियत अचानक खराब हो गई है। रायपुर आ जाओ। परिजनों के साथ जब रायपुर के मेकाहारा पहुंचा तो भाई को मृत हालत में पाया। मेकाहारा में लोकल ठेकेदार मिला, जिसने बताया, कि मिट्टी के ढेर के नीचे वो दब गया था। इलाज के लिए जब तक उसे अस्पताल पहुंचाते उसने दम तोड़ दिया।

तीन बेटियों का पिता है गुड्डू

मृतक के परिजनों ने बताया, कि गुडड् रवि की तीन बेटियां है। एक बेटी पांच साल की, दूसरी तीन साल और तीसरी नौ महीने की है। गुड्डू की मौत की जानकारी मिलने पर पत्नी माया देवी बदहवास है। परिजनों ने मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस और रायपुर निगम की टीम सामान करेगी जब्त, जोनवार चलेगा अभियान

सड़क पर कब्जा किया तो अब FIR होगी दर्ज

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में सड़क और बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। रायपुर निगम और पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि, सड़क पर कब्जा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अब सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही सड़क पर रखा सामान जब्त कर लिया जाएगा। इसके लिए शहर में जोनवार अभियान चलाया जा रहा है।

रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप और यातायात एसपी अजय कुमार के मार्गदर्शन में टीमों ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। एएसपी यातायात विवेक शुक्ला, नगर निगम के अपर आयुक्त पंकज के. शर्मा समेत नगर निवेश और उड़नदस्ता की टीमों ने बुधवार को जोन क्रमांक-4 के मालवीय मार्ग और जोन-5 के पुरानी बस्ती मार्ग व लाखेनगर चौक क्षेत्र में कार्रवाई की।

मना करने के बावजूद हो रहा अतिक्रमण

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि, बार-बार समझाइश के बावजूद जो दुकानदार नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही यातायात बाधित करने वाले सभी सामानों को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की होगी। प्रशासन का कहना है कि "टीम प्रहरी" अभियान के तहत शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने की लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

भाजपा सरकार स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद करना चाह रही- कांग्रेस

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से आत्मानंद स्कूल को बंद करने का षडयंत्र शुरू कर दिया गया है अभी कुछ सालों में आत्मानंद स्कूलों में स्टेशनरी की कमी, आवश्यक सुविधा को उपलब्ध नही कराया जा रहा है।

स्कूलों के शिक्षकों को जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से वेतन नहीं दिया जा रहा ताकि संविदा के आधार नियुक्त शिक्षक धनाभाव में स्कूल छोड़ दें और स्कूलों को बंद करने का बहाना खोजा जा सके। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि विधानसभा में सरकार ने घोषणा कर दी है कि आत्मानंद स्कूल में प्री-प्राइमरी की कक्षाएं बंद कर दी जायेगी। आत्मानंद स्कूल ऐसा माध्यम था जहां गरीबों के बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करते थे लेकिन भाजपा की फासीवादी सोच राजनैतिक दल नहीं चाहता कि गरीब के बच्चों को स्तरीय शिक्षा मिले। इसलिये आत्मानंद स्कूल को बंद करने की साजिश की जा रही है। पहले पायदान के तौर में प्री-प्राइमरी कक्षा को बंद किया है।

गृहमंत्री बंगले में नक्सलियों को भोजन और आर्म्स फोर्स के वेटिंग कैंडिडेट को गिरफ्तार करवाते हैं: धनंजय सिंह

शहर सत्ता/रायपुर। गृहमंत्री से मिलने जा रहे छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स के वेटिंग कैंडिडेट को गिरफ्तार करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा आखिर छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स के वेटिंग कैंडिडेट से मिलते क्यो नही है?गृहमंत्री जब अपने बंगले में आत्म समर्पित नक्सलियों के साथ बैठकर कर दो बार भोज कर सकते है उनके लिए लाल कारपेट बिछा सकते है ऐसे में छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स के होनहार कैंडिडेट से मिलकर उनकी समस्या का निराकरण क्यो नही कर रहे है?108 दिन से वेटिंग कैंडिडेट नोकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे है?जब भी केंडिडेट गृहमंत्री से मिलने जाते है पुलिस बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाता है ?

बिजली बिल ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया - कांग्रेस

शहर सत्ता/रायपुर। बढ़े बिजली बिल ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि चार महिने से आ रहे बेतहाशा बढ़ा बिजली बिल से राज्य का हर नागरिक परेशान है। 200 यूनिट हाफ बिजली योजना से भी कोई राहत नहीं है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार भूपेश सरकार के समय शुरू की गयी बिजली बिल हाफ योजना को फिर शुरू करें, ताकि जनता को बढ़े बिजली बिल में कुछ राहत मिल सके। बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के कारण जनता बिजली के बिल नहीं पटा पा रही उनकी लाईन काटी जा रही। प्रदेश में हजारो उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की नाकामी लापरवाही और मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण प्रदेश के लोगों के लिए बिजली कटौती और मंहगी बिजली बड़ी समस्या बन गई है।

भाजपा बताये छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी कब लागू होगी - बैज

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि शराब बंदी को लेकर पांच सालों तक हल्ला मचाने वाले भाजपाई बताएं शराबबंदी कब होगी? भाजपा के हर छोटे बड़े नेता ने जनता के बीच घूम-घूम कर शराबबंदी के लिये बढ़ चढ़कर बातें किया था। सरकार में आने के बाद सरकार और भाजपाइयों दोनों के जुबान पर ताला लग गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में शराब के नाम पर वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। दुकानों में कौन सी शराब बिकेगी, कौन से निर्माता के ब्रांड राज्य में बिकेगा, इसके नाम पर कमीशन खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है। शराब के इस सुनियोजित घोटाले में उच्च स्तर के लोग संलिप्त है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने 67 नई शराब दुकाने शुरू कर दिया।

महिला की 12 पसलियां टूटीं, दिल-फेफड़े फटे

सिर की 3 हड्डियां भी टूटी, अंबिकापुर में प्रेमी ने रेप के बाद दी दर्दनाक मौत

शहर सत्ता/अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रेमी ने रेप के बाद महिला की सिर कुचलकर हत्या कर दी। उसके प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक की बोतल डाल दी। करीब 10 साल पहले महिला के पति की मौत हो गई थी। वारदात से पहले दोनों साथ में जाते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। पोस्टमॉर्टम करने वाले मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग के डॉ. संटू बाघ ने बताया कि, महिला के सीने की 12 पसलियां पूरी तरह टूट गई थी। पसली की हड्डियों के कई टुकड़े हो गए थे। इससे महिला का फेफड़ा और दिल फट गया था।

इसके अलावा सिर में भी 3 जगह गंभीर चोट आई है। सिर की तीन हड्डियां टूटी हुई थीं। गले को भी दबाया गया है। जिस तरह के चोट दिखाई पड़े हैं, उससे संभावना है कि उसके सीने पर चढ़कर काफी दबाव दिया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि घटना में एक से ज्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। शुरुआती रिपोर्ट में महिला से दुष्कर्म की बात सामने आई है। पुष्टि के लिए बिसरा जांच के लिए भेजा गया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

CCTV में कैद हुआ आरोपी

इस मामले की जांच कर रही पुलिस को कुछ CCTV फुटेज मिला है, जिसमें महिला और आरोपी रात करीब 1 बजे घटना स्थल की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। महिला अपने प्रेमी के कंधे पर हाथ भी रखी हुई थी। घटनास्थल पर पर्दा लगा था। जिसके पीछे दोनों ने खाना भी खाया था। एक फूटेज में प्रेमी का चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा है। पुलिस ने उसकी पहचान पांडा उर्फ मिथुन के रूप में की है। फिलहाल, उसकी तलाश जारी है।

सिंहदेव बोले- आखिर किस बात का सुशासन

इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि, अंबिकापुर की एक बेटी के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यह हैवानियत दिल्ली के निर्भया कांड की तरह दिल दहला देने वाली है। क्रोध भी है, पीड़ा भी है, और एक गहरा सवाल भी-क्या हमारी बेटियां अब सड़कों पर भी सुरक्षित नहीं? सिंहदेव ने कहा कि, जब शहर का सबसे व्यस्त इलाका भी सुरक्षित नहीं, तो यह सरकार आखिर किस बात का शासन चला रही है?

महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर हस्ताक्षर अभियान चलाया

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते क्राइम के विरोध में सरगुजा जिला महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। महिला कांग्रेस ने शहर के कई चौक-चौराहों पर जाकर 11 मीटर की श्वेत साड़ी में लोगों से उनका हस्ताक्षर लेकर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भेजने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के महामाया प्रवेश द्वार के पास रिंग रोड किनारे स्थित झोपड़ीनुमा मटन की दुकान है। जहां शुक्रवार (3 अप्रैल) सुबह एक महिला का शव खून से लथपथ पड़ा था। स्थानीय लोगों ने देखा तो थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही एसएसपी राजेश अग्रवाल, एएसपी अमोलक सिंह, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची।

बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद 95% तक जली मिली छात्रा, मौत

शहर सत्ता/रायपुर/सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बॉयफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद 11वीं की छात्रा 95% तक जली हुई हालत में मिली, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है दोनों ने मिलकर किश्त में नया मोबाइल खरीदा था। छात्रा ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया तो बॉयफ्रेंड ने उसका फोन छिन लिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र का है। विवाद के अगले दिन विश्रामपुर-भटगांव रोड किनारे छात्रा की आधे से ज्यादा जली हुई मिली। लड़की का हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया था, जहां रविवार (5 अप्रैल) सुबह उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सुसाइड की आशंका जताई है। वहीं बॉयफ्रेंड से पूछताछ भी की जा रही। पूछताछ के बाद पुलिस ने भूपेंद्र सिंह को थाने में बैठा लिया है। पुलिस भूपेंद्र सिंह के बयान की जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस को छात्रा की मौत की अधिकारिक सूचना नहीं मिली है। शनिवार (4 अप्रैल) सुबह करीब 9 बजे विश्रामपुर-भटगांव रोड पर पासिंग नाले के पास सड़क किनारे नाबालिग जली अवस्था में मिली थी। उसकी पहचान ग्राम गोरखनाथपुर निवासी मोनिका सिंह उर्फ मोना (17) के रूप में हुई। वो कक्षा 11वीं की छात्रा थी। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे 95 फीसदी जलना बताया गया। उसे शुरुआती इलाज के बाद अंबिकापुर रेफर कर दिया गया था। सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे।

- **किश्त पर खरीदे मोबाइल छीनने पर हुआ था विवाद, सुसाइड की धमकी दी थी**

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े परिजनों से मिलीं

घटना की सूचना पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शनिवार शाम अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंची। मोनिका सिंह को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कराया। उसे रात में ही रायपुर मेकाहारा भेज दिया गया।

7 साल के बच्चे से दुष्कर्म, चिल्लाने पर पत्थर से कुचला सिर, कुएं में फेंका शव

शहर सत्ता/कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 7 साल के बच्चे से गलत हरकत के बाद मर्डर हुआ है। मासूम तालाब में नहा रहा था। इस दौरान पड़ोसी रंजीत कुमार (19) की नीयत बिगड़ गई। आरोपी उसे बहलाकर सुनसान जगह ले गया, जहां बच्चे का पैंट उतारकर उसने गंदी हरकत की। विरोध करने पर मार डाला।

मामला पाली थाना के ग्राम पंचायत डोंगानाला के आश्रित ग्राम गणेशपुर का है। आरोपी ने पोल खुलने के डर से बच्चे के सिर पर पत्थर से 4 बार हमला किया। वारदात के बाद शव 12 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया था। घटना के 2 दिन बाद बच्चे की लाश मिली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रंजित ने बताया कि आयान का शव पड़ोसी

गांव करतली के एक खेत में बने कुएं में है। यह सुनते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी की निशानदेही पर कुएं से बच्चे का शव बरामद कर लिया।

पुलिस को शुरू से ही शक था कि बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हुई है और उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंका गया है। इसी शक के आधार पर पुलिस ने रंजीत से फिर से सख्ती से पूछताछ की। 4 अप्रैल को मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी नागेश तिवारी खुद गांव पहुंचे, उन्होंने रंजीत से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में आखिरकार रंजीत टूट गया और उसने सच उगल दिया।

गृहमंत्री से मिलने गए CAF कैंडिडेट्स गिरफ्तार, तीन जेल गए

- **अभ्यर्थी बोले- तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की झूठी FIR दर्ज हुई**

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स (CAF) के वेटिंग कैंडिडेट पिछले 108 दिनों से नौकरी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान वे कई बार गृहमंत्री विजय शर्मा से मिलने उनके बंगले भी पहुंचे। दो-तीन बार मुलाकात तो हुई, लेकिन अब तक उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। शनिवार को तीन कैंडिडेट्स एक बार फिर से गृहमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। लेकिन तीनों को पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने और नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार कर दिया।

इसके बाद से तीनों जेल में हैं। दूसरे कैंडिडेट्स का कहना है कि पुलिस ने झूठे आरोप लगाकर FIR दर्ज की है। तीनों सिर्फ बातचीत करने गए थे, गृहमंत्री तो मिले नहीं। लेकिन झूठा केस दर्ज कर तीनों को जेल जरूर भेज दिया गया। अन्य कैंडिडेट्स का आरोप है कि शासन उनका प्रदर्शन समाप्त करना चाहती है। इसलिए इस तरह का दबाव डालकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि कैंडिडेट्स ने ये भी स्पष्ट किया है कि वो अपनी मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखेंगे।

मंत्रियों को खून से लिखा पत्र

कैंडिडेट्स ने इससे पहले अलग-अलग मंत्रियों को खून से पत्र लिखकर नौकरी की मांग की थी। कैंडिडेट्स का कहना है गृहमंत्री के अधिकारी उन्हें मंत्री शर्मा से मिलने ही नहीं दे रहे हैं। दरअसल, पहली मुलाकात में गृहमंत्री ने कैंडिडेट्स को कोर्ट जाने को कह दिया था। दूसरी मुलाकात में उन्होंने सीएम से पूरे मामले में बात करने का आश्वासन दिया था। तीसरी मुलाकात में उन्होंने कैंडिडेट्स को बताया था कि सीएम से बात नहीं हो पाई है। वो बात करेंगे। बातचीत का अपडेट जानने के लिए ही कैंडिडेट्स लगातार गृहमंत्री हाउस पहुंच रहे हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उनकी मांग को सही बताया है। उनके समर्थन में लेटर भी लिख चुके है। लेकिन गृहमंत्री के यहां से उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है।

'प्रोफेसर' गैंग को ड्रग्स सप्लाई करता था 'भूतनाथ'

रायपुर में 'डेड ड्रॉप सिस्टम' से हो रही थी डिलीवरी

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सूखा नशा और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी मामले में पुलिस ने दिल्ली से 2 आरोपियों को पकड़ा था। आरोपी 'प्रोफेसर गैंग' से जुड़े हुए थे। इन आरोपियों ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। आरोपियों ने बताया कि वे दिल्ली में एक्टिव कुख्यात 'भूतनाथ गैंग' से ड्रग्स लेकर कोरियर सर्विस के जरिए रायपुर और दूसरे शहरों में सप्लाई करते थे। जांच में यह भी पता चला है कि 'भूतनाथ' नाम का आरोपी विदेशी नागरिक है, जो नाइजीरियन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया है कि ड्रग्स सिंडिकेट के मास्टरमाइंड महेश खड़का और कुसुम हिन्दुजा दिल्ली में बैठकर पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। ये दोनों आरोपी कोरियर के जरिए एमडीएमए, पार्टी पिल्स और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स रायपुर भेजते थे। रायपुर में 'डेड ड्रॉप सिस्टम' से ड्रग्स की डिलीवरी की जा रही थी। बता दें कि इससे पहले भी रायपुर पुलिस ने 'प्रोफेसर गैंग' और नाव्या मालिक जैसे मामलों में कार्रवाई करते हुए इसी नेटवर्क की कड़ियां उजागर की थीं।

'भूतनाथ' निकला विदेशी नागरिक, नाइजीरियन कनेक्शन

पुलिस के मुताबिक 'भूतनाथ' नाम से पहचाना जाने वाला आरोपी असल में एक विदेशी नागरिक है, जो दिल्ली से इस पूरे सिंडिकेट को संचालित कर रहा था। यह गैंग नाइजीरियन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। एमडीएमए, कोकीन जैसे महंगे नशीले पदार्थों की सप्लाई छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में करता है। दिल्ली के पटपड़गंज और महिपालपुर इलाके इसके ऑपरेशन के मुख्य ठिकाने बताए जा रहे हैं। लोकल और विदेशी नागरिकों की मदद से इस सिंडिकेट को चलाया जा रहा है।

दुबई से व्हाया दिल्ली, छत्तीसगढ़ तक ड्रग्स रूट

जानकारी के मुताबिक, इस ड्रग्स नेटवर्क की जड़ें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई हैं। ड्रग्स की खेप दुबई से भारत भेजी जाती है। गुजरात

में रिफाइनिंग के बाद दिल्ली पहुंचती है। फिर 'भूतनाथ गैंग' के जरिए कोरियर नेटवर्क से रायपुर और अन्य राज्यों में सप्लाई होती है। इस पूरे नेटवर्क में कोडवर्ड, फर्जी पहचान और डिलीवरी एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था।

कोरियर बॉक्स और डिजिटल सिस्टम से सप्लाई

आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि, ड्रग्स सप्लाई के लिए कोरियर बॉक्स, डिजिटल पेमेंट और लोकेशन शेयरिंग जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पुलिस को चकमा देने की कोशिश की जाती थी। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि, आरोपी 'Dead Drop System' का इस्तेमाल कर रहे थे। इस सिस्टम में ड्रग्स को सुनसान स्थानों पर रखकर उसकी लोकेशन और वीडियो ग्राहकों को भेज दी जाती थी। ग्राहक वहां से जाकर ड्रग्स उठा लेते थे।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

साय या गाय

किसी को सबसे मूल्यवान चीज जो हम दे सकते हैं, वह अतिरिक्त फूड या फंड नहीं, बल्कि यह सुकून है कि वे अकेले नहीं हैं। रजत वर्ष मना रहा छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जिनकी कोई किचन कैबिनेट नहीं है। राजनैतिक-चारित्रिक अध्ययन करें तो पूरवर्ती कार्यकाल में सबसे लंबी सियासी पारी खेलने वाले डॉ रमन सिंह बतौर मुख्यमंत्री शुरुआती तीन साल तक गाय से सीधे लगे। राज्य गठन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी नाम फाइनल होने से पहले गाय बने रहे। कमोबेश भूपेश बघेल भी कभी गाय से दुलारे और यदाकदा गुस्साए सांड जनता को परिलक्षित हुए। उक्त सभी राजनेताओं ने बाद में विरोधियों को जाता दिया वो सीधी-सादी और दुधारू गाय नहीं हैं। ये अकेले भी नहीं रहे कैबिनेट के साथ इनकी किचन कैबिनेट भी खासी चर्चित रही। छत्तीसगढ़ के सूबा-ऐ-सदरों की इस फेहरिस्त में सुशासन के पैरोकार विष्णु देव साय भी हैं। लेकिन कमोबेश वे सुबाई सियासत में पहले भी गाय और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गाय से लगते हैं।

साय जी को समझना और जनता को समझाना भी होगा कि वो गाय नहीं हैं। उन्हें सदर बनें खासा वक्त भी हो चला है और अब उनका भी किचन केबिनेट होना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें सब अपने लगते हों लेकिन जरुरी नहीं की सब उन्हें भी अपना सा स्नेह दें। फ़िलहाल छत्तीसगढ़ की बागडोर उनके हाथों में है और उन्हें यह जगजाहिर करना होगा कि वे पार्टी के लिए दुधारू गाय भी हैं, छत्तीसगढ़ियों के लिए कामधेनु स्वरुप भी हैं और गलत राह पकड़ चुके सहमंत्री के लिए बौराए सांड भी बन सकते हैं। लब्बोलुआब यह कि नक्सलवाद समाप्ति की क्रेडिट प्रदेश की कम और केंद्र की ज्यादा लगती है। किसानों के खेत में लहलहाती अफीम-गांजे की फसल उनकी दें नहीं है यह साबित करना होगा। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार उन सभी विभागों और विभागीय मंत्रियों की मुश्कें भी कसना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी उनकी किचन कैबिनेट के तो सब हैं भी नहीं।

गाय ही सहीं लेकिन आप साय भी अब बन जाइए क्योंकि चुनावी वर्ष आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। साय कैबिनेट को जीरो टॉलरेंस सिर्फ स्लोगन नहीं मुरुगन स्टाइल में अपनाना होगा। खासकर सवास्थ्य मंत्री, राजस्व मंत्री, कृषि एवं आदिमजाति विभाग मंत्री समेत महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री पर चुनावी वर्ष से पहले पैनी नजर रखने की दरकार है। यह काइंडनेस-फंड के लिए भी जरुरी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि विपक्ष को मुद्दा और भविष्य में विधानसभा सत्र साय या गाय पर ही हंगामाख़ेज़ रहे। आपको अब बताना होगा की गाय को हर कोई दुह नहीं सकता और गाय के पास सींग भी होती है और अपने बच्चे की हिफ़ाज़त शिद्दत से करना भी जानती है।

क्या राजनीतिक सरप्राइज देंगे चुनावी नतीजे

अवधेश कुमार

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का अभियान इस समय चरम पर है। चुनाव किसी भी स्तर का हो, पिछले कुछ वर्षों में उसकी राष्ट्रीय परिणीति दिखाई देती ही है। है। गहराई से देखें तो इन पांचों राज्यों में स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर एसआईआर, चुनाव आयोग, हिंदुत्व, यूजीसी नियमन जैसे राष्ट्रीय विषय हर जगह आच्छादित हैं। ऐसे में इनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस वर्ष का यह पहला चुनावी दौर है। पिछले लोकसभा चुनाव से अभी तक झारखंड को छोड़कर सभी विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सफलता प्राप्त की।

प्रांतीय चुनावों ने इस सोच को 360 डिग्री मोड़ दिया। विपक्ष के खेमे में घोर हताशा है जबकि भाजपा और राजग के अंदर उत्साह और उम्मीद चरम पर है। इस चुनाव में विपक्ष सफलता प्राप्त करेगा तो देश में मनोवैज्ञानिक रूप से वातावरण बनाने की कोशिश करेगा। क्या भाजपा का प्रदर्शन इन पांचों राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही अपेक्षित है? इसका सीधा उत्तर है, नहीं। तो फिर? इन पांच राज्यों में असम में पिछले 10 वर्षों से उसकी सरकार है और पुडुचेरी जैसे छोटे स्थान में भाजपा सरकार में शामिल है। तमिलनाडु में तो वह एक छोटी पार्टी के रूप में लड़ रही है। केरल में किसी को उम्मीद नहीं है कि भाजपा सत्ता में आ सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जबरदस्त उपस्थिति 2018 के स्थानीय निकाय चुनाव से दिखाई है और विधानसभा में पिछली बार उसने 77 सीटें जीती। भाजपा के पक्ष और विपक्ष में वातावरण के मूल्यांकन की एकमात्र कसौटी असम में उसका प्रदर्शन होगा। इसके अलावा उसने अगर पिछले चुनाव से बेहतर किया तो फिर इसका निष्कर्ष राष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का अभियान इस समय चरम पर है। चुनाव किसी भी स्तर का हो, पिछले कुछ वर्षों में उसकी राष्ट्रीय परिणीति दिखाई देती ही है। गहराई से देखें तो इन पांचों राज्यों में स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर एसआईआर, चुनाव आयोग, हिंदुत्व, यूजीसी नियमन जैसे राष्ट्रीय विषय हर जगह आच्छादित हैं। ऐसे में इनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस वर्ष का यह पहला चुनावी दौर है। पिछले लोकसभा चुनाव से अभी तक झारखंड को छोड़कर सभी विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सफलता प्राप्त की। बिहार पिछले वर्ष का अंतिम चुनाव था, जिसमें भाजपा जद यू और अन्य दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने ऐसी विजय प्राप्त की, जिसकी कल्पना उसके घोर समर्थक भी नहीं कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने ऐसा माहौल बनाया था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और राजग के राष्ट्रीय और राज्यों की राजनीति में प्रभावी रहने के दिन गिने-चुने बचे हैं।

इस चुनाव के बीच खाड़ी में युद्ध चल रहा है। इसका प्रभाव हमारे देश में भी है। यद्यपि पेट्रोल-डीजल, पीएनजी-सीएनजी की अभी तक देश में कमी नहीं है, किंतु विरोधियों ने लगातार ऐसा वातावरण बनाया है, जैसे देश मोदी सरकार की नीतियों के कारण संकट में फंस गया है। यह सभी राज्यों में विपक्ष की ओर से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा चुका है। हालांकि अफवाह नहीं हो तो देशव्यापी ऐसी शिकायत नहीं कि किसी की गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं मिला या कहीं पीएनजी, सीएनजी की आपूर्ति में कमी है। एलपीजी की समस्या है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं आई जिसमें किसी को अपने घर में खाना बनाने में समस्या हो। अब चूंकि विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है, वातावरण बना हुआ है तो यह नहीं कह सकते कि चुनाव इससे प्रभावित बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमन के विरुद्ध सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के विरुद्ध देशव्यापी वातावरण बनाने की कोशिश हुई और इसका भी असर है।

कोई पार्टी इसके विरोध में नहीं है, कांग्रेस ने इसका समर्थन कर दिया, बावजूद सबकी कोशिश है कि वातावरण बना रहे और हम इसके समर्थन या विरोध में न बोलें ताकि इससे भाजपा और उसके सहयोगियों को क्षति हो। इसके विरोधी दूसरे राज्यों में जाकर भी भाजपा के विरुद्ध सभाएं कर रहे हैं या यह कह सकते हैं कि विरोधी दलों द्वारा उन्हें प्रायोजित किया गया है। तीसरा मुद्दा चुनाव आयोग और एसआईआर है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस इन दोनों ने इसे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। हालांकि बिहार में इसका कोई असर नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल का मामला अलग है। सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय दे चुका है। मालदा में एसआईआर के काम करने वाले न्यायिक अधिकारियों को रातभर बंद करने का संज्ञान लेने के बावजूद वहां तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने चुनाव आयोग और एसआईआर के विरोध में ऐसा वातावरण बना दिया है, जिसमें उन्हें अपेक्षित सहयोग और अनुकूल वातावरण नहीं मिला। बंगाल में अगर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तथा अन्य विपक्षी दल हमलावर होकर बोलेंगे कि चुनाव आयोग और एसआईआर के बावजूद लोगों ने इन्हें निकाल दिया। अब इन्हें इस प्रक्रिया को वापस लेनी चाहिए। अगर भाजपा ने बढ़िया प्रदर्शन कर दिया तो यही कहा जाएगा कि एसआईआर के कारण मतदाताओं के नाम कटवा कर जीती है और चुनाव आयोग की इसमें भूमिका है। लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव भेजा हुआ है। दोनों परिस्थितियों में विपक्ष चुनाव के बाद एसआईआर और चुनाव आयोग के विरुद्ध अभियान चलाएगा। वैसे अभी तक की गणना में सबसे ज्यादा नाम तमिलनाडु में कटे हैं। वहां भी मुद्दा है पर पश्चिम बंगाल की तरह नहीं। चौथा, इस बार हर राज्य में हिंदुत्व और मुस्लिम कट्टरवाद मुद्दा है।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी समारोह के मार्च लगातार रोकने की कोशिश हुई। बंगाल और असम दोनों जगह घुसपैठ को भाजपा ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। बंगाल में ही तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता और विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। तमिलनाडु में फिल्म स्टार विजय के आने से मामला त्रिकोणीय हुआ है। अगर वहां विजयकांत अच्छा करते हैं तो भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में उसका महत्व बढ़ेगा। इस तरह पांच राज्यों में चुनाव राष्ट्रीय राजनीति में मुद्दे, पक्ष-विपक्ष के बीच संबंध, आंशिक रूप से राजनीतिक समीकरण तथा हिंदुत्व सनातन की दृष्टि से स्पष्ट दिशा देने वाला हो सकता है।

तृणमूल संग सीधी स्पर्धा में भाजपा का पलड़ा भारी

विकेश कुमार बडोला

पश्चिम बंगाल की राजनीति में प आजकल बड़ा मुद्दा यही है कि क्या ममता का दुर्ग दरक रहा है? राज्य की राजनीतिक स्थिति वर्तमान में एक ऐसे मोड़ पर है, जहां सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बौखलाहट केवल राजनीति से प्रेरित बयानबाजी नहीं, बल्कि गहरे जमीनी बदलावों का संकेत दे रही है। 2011 में परिवर्तन का नारा देकर वामपंथ के अभेद्य किले को ढहाने वाली ममता आज स्वयं वैसी ही घेराबंदी का सामना कर रही हैं, जैसी उन्होंने कभी बुद्धदेव भट्टाचार्य के विरुद्ध की थी।

यदि 2016 से लेकर 2021 तक के चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण करें तो तृणमूल के प्रति मूल बंगालियों में अविश्वास उत्पन्न हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से बंगाल के चुनावी परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। जहां पहले स्पर्द्धा वामपंथ और तृणमूल के बीच थी, वहां अब वामपंथ का स्थान भाजपा ने ले लिया है। आंकड़ों को देखें तो 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 44.91 प्रतिशत मतों के साथ 211 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा मात्र 10.16 प्रतिशत वोट और 3 सीटों पर सिमट गई थी। उस समय वाम मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को लगभग 32 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। हालांकि, 2021 के विधानसभा चुनाव तक आते-आते स्थिति पूरी तरह बदल गई। तृणमूल ने 47.94 प्रतिशत मतों के साथ 215 सीटें हासिल कीं, लेकिन भाजपा का मत प्रतिशत 10 से बढ़कर सीधे 38.13 प्रतिशत पर पहुंच गया और उसकी सीटों की संख्या 3 से बढ़कर 77 हो गई। आश्चर्य ये रहा कि वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन मात्र 10 प्रतिशत मतों और 1 सीट पर सिमट कर रह गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भाजपा अब राज्य में कोई अस्थायी लहर नहीं बल्कि एक स्थायी और शक्तिशाली विपक्ष बन चुकी है। बंगाल की राजनीति में अवैध घुसपैठिए और मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से निर्णायक कारक रहे हैं।

राज्य की लगभग 27 से 30 प्रतिशत मुस्लिम आबादी पर तृणमूल का गहरा प्रभाव रहा है। हालांकि, निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे कड़े मतदाता पुनरीक्षण ने तृणमूल की रणनीतियों को प्रभावित किया है। निर्वाचन सूचियों से फर्जी और दोहरी प्रविष्टियों का हटना ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विशेषकर सीमावर्ती जिलों जैसे उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद में यदि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नाम सूचियों से हटते हैं, तो इसका सीधा असर तृणमूल के सुरक्षित वोट बैंक पर पड़ेगा। हाल के वर्षों में भारतीय सेक्युलर फ्रंट के उभार और मुस्लिम समुदाय के भीतर बढ़ते असंतोष ने यह संकेत दिया है कि यह वोट बैंक अब विभाजित हो सकता है। यदि मुस्लिम मतों में 5 से 7 प्रतिशत की भी गिरावट आती है, तो दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को सीधा लाभ मिल सकता है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

ईरान में 'मिशन इम्पॉसिबल' जैसा ऑपरेशन, पायलट को सुरक्षित निकाला

ईरान का दावा, 'पायलट को रेस्क्यू करने आए अमेरिका के C-130 एयरक्राफ्ट को मार गिराया

ईरान के भीतर अमेरिकी सेना ने एक बेहद जोखिम भरा और साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया. अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज ने शनिवार रात ईरान में फंसे अपने एक लापता एयरफोर्स ऑफिसर को सुरक्षित निकाल लिया. इस पूरे मिशन में रेस्क्यू टीम का कोई भी सदस्य हताहत नहीं हुआ और घायल ऑफिसर को इलाज के लिए सीधे कुवैत भेज दिया गया है.

F-15E जेट गिराए जाने के बाद फंसा था ऑफिसर

दरअसल, शुक्रवार को ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को मार गिराया था. जेट गिरने के बाद दोनों क्रू मेंबर्स ने इजेक्ट कर लिया था. पायलट को जल्द ही बचा लिया गया, लेकिन वेपन्स सिस्टम्स ऑफिसर दुश्मन के इलाके में फंस गया. वह लगभग एक दिन तक सिर्फ एक पिस्तौल के सहारे छिपा रहा. इस दौरान ईरानी सेना ने उसे ढूंढने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी और स्थानीय लोगों को इनाम का लालच भी दिया गया था. हालांकि, जिस इलाके में जेट गिरा था, वहां सरकार के खिलाफ विरोध होने के कारण ऑफिसर को छिपने में मदद मिली.

रेस्क्यू मिशन के लिए सैकड़ों कमांडो तैनात

ईरान में फंसे ऑफिसर को निकालने के लिए अमेरिकी सेना के कई अधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें अंततः सैकड़ों अमेरिकी कमांडो को इस मिशन के लिए चुना गया. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस ऑपरेशन में सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशंस टूप्स शामिल थे. इसके साथ ही दर्जनों युद्धक विमान, हेलिकॉप्टर, साइबर, स्पेस और अन्य इंटेलिजेंस क्षमताओं का इस्तेमाल किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान में फंसा अमेरिकी ऑफिसर एक बीकन और सुरक्षित कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से रेस्क्यू टीम के संपर्क में था. जब अमेरिकी कमांडो ऑफिसर के करीब पहुंचे, तो वहां जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई. अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ऑफिसर की लोकेशन के पास बढ़ रहे ईरानी काफिलों पर बमबारी की, ताकि उन्हें दूर रखा जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सके.

अमेरिका के कई विमान नष्ट किएः ईरान

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच करीब अमेरिकी सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर 48 घंटे तक छिपे रहने के बाद अपने एयरफोर्स ऑफिसर को सुरक्षित बचा लिया. ईरान का कहना है कि अमेरिकी पायलट को बचाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 लोग मारे गए और दुश्मन के कई विमान नष्ट किए गए. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने कहा कि एक फंसे हुए सैनिक का पता लगाने के लिए चलाए गए अमेरिकी अभियान के दौरान कई विमान तबाह किए गए. IRGC के तहत संचालित खातम अल-अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी बताया कि इस्फहान के दक्षिण में पायलट को बचाने का अमेरिकी मिशन फेल हो गया. ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन के दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 सपोर्ट विमान को मार गिराया गया, जिसमें 5 लोग मारे गए।

ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम का दिया जवाब

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज जलडमरूमध्य खोलने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन तेहरान ने इस चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया. ईरान ने साफ कहा है कि वह किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है और इस तरह की धमकियों का जवाब देगा.अमेरिका की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और इजरायल, ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं. यह संघर्ष फरवरी के अंत में संयुक्त हमलों के बाद शुरू हुआ था. इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें वॉशिंगटन की मंजूरी का इंतजार है.

अमेरिकी और ईरानी सेनाएं दो अमेरिकी लड़ाकू विमानों के गिराए जाने के बाद एक लापता अमेरिकी क्रू मेंबर की तलाश कर रही हैं. यह स्थिति दिखाती है कि जंग में खतरा लगातार बढ़ रहा है, भले ही अमेरिका हवाई बढ़त का दावा कर रहा हो.ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को काफी हद तक बंद कर दिया है, जो दुनिया के लिए तेल आपूर्ति का एक अहम रास्ता है. इसके चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है. इस बीच, संघर्ष और फैल गया है. ईरान, इजरायल और उनके सहयोगी समूहों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं.डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान या तो समझौता करे या 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज जलडमरूमध्य खोल दे।

पीएम की हुंकार, कट, कमीशन और करप्शन से बंगाल बेहाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून-व्यवस्था और घुसपैठ के मुद्दे को लेकर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में खतरनाक बदलाव आया है क्योंकि घुसपैठियों को टीएमसी का सीधा संरक्षण मिलता है. सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले बंगाल में लोग रोजगार के लिए आते थे, लेकिन निर्मम सरकार ने उसी बंगाल को पलायन का केंद्र बन दिया है.

पीएम मोदी ने कहा, 'ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके, उल्टे टीएमीस सीएए को रद्द करने की धमकी दे रही है. यानि जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे और वो ये नागरिकता घुसपैठियों को देंगे. क्योंकि टीएमसी घुसपैठियों को अपना वोटबैंक मानती है. इन घुसपैठियों को टीएमसी का सीधा संरक्षण मिलता है. टीएमसी इन्हें सीधे अपने सिंडिकेट में भर्ती करती है. टीएमसी बंगाल में कानून-व्यवस्था का जनाजा निकालने पर तुली है.' उन्होंने कहा, 'मैं कूच बिहार से देश के सभी राज्यों को मैं फिर याद दिलाता हूं कि जिन भी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है उनको सीटों के विषय में कोई नुकसान नहीं होगा, सभी का फायदा ही होगा. सभी राज्यों की भागीदारी और सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे. हम संसद में इसपर पक्का ठप्पा लगाना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़े।

टीएमसी ने उर्दू में जारी किया मेनिफेस्टो ममता बेनर्जी पर भड़के गिरिराज सिंह

कहा- बंगाल को बांग्लादेश बनाने का एजेंडा

नई दिल्ली। जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे राज्य की सियासत को लेकर राजनीतिक गहमागहमी भी बढ़ती जा रही है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के घोषणापत्र को जारी कर दिया है, लेकिन टीएमसी ने अपना चुनावी घोषणापत्र सिर्फ उर्दू भाषा में जारी किया है, इसलिए इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है.भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने टीएमसी के उर्दू भाषी घोषणा पत्र को लेकर ममता बनर्जी पर भाषायी और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस कदम को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, बिहार की राजधानी पटना में शनिवार (4 अप्रैल, 2026) को मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने सिर्फ उर्दू में घोषणापत्र जारी नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे टीएमसी का एक छिपा हुआ एजेंडा भी है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह एजेंडा शरिया कानून से जुड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाने की एक सोची-समझी योजना के तहत काम किया जा रहा है.

उन्होंने दावा किया कि अब राज्य के लोगों, विशेषकर हिंदू समुदाय, ने इस कथित वास्तविक चेहरे को अच्छे से पहचान लिया है. इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए जीओ या मरो की स्थिति जैसा बन गया है. उनका आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी और ऐसी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर मतदान करेगी.

हैप्पीनेस इंडेक्स में 116वें स्थान पर भारत

दुनिया का सबसे दुखी देश है अफगानिस्तान

दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची जारी हो चुकी है. हालांकि, इसमें कुछ ऐसे देश शामिल है, जो सबसे ज्यादा नीचे हैं. अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और लेबनान जैसे देशों में हालात काफी खराब बताए गए हैं. यह रिपोर्ट सिर्फ पैसे या अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ी कई बातों को देखकर तैयार की गई है. इसमें जीवन से संतुष्टि और सामाजिक हालात जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार कई देशों का स्कोर 4 से भी नीचे चला गया है, जो बताता है कि वहां के लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं. खास तौर पर अफगानिस्तान का स्कोर सबसे कम है, जो इस सूची में सबसे नीचे है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, अफगानिस्तान 147वें स्थान पर है और उसका स्कोर सिर्फ 1.446 है. इसमें -2.594 की गिरावट दर्ज की गई है, जो सबसे ज्यादा है. इसका मतलब है कि वहां हालात तेजी से खराब हुए हैं. वहां की जिंदगी आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी सुविधाओं की कमी से प्रभावित है. इस सूची में भारत 116वें स्थान पर काबिज है.

अफ्रीका के देशों की स्थिति

सिएरा लियोन 146वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 3.251 है और इसमें -1.067 की गिरावट आई है. यह देश कई सालों से संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य और ढांचे जैसी सुविधाओं पर दबाव बना हुआ है. मलावी 145वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 3.284 है और -0.829 की गिरावट दर्ज की गई है. यहां आर्थिक सीमाएं, मौसम से जुड़ी समस्याएं और संसाधनों की कमी लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं. खासकर गांवों में हालात ज्यादा कठिन बताए जाते हैं. जिम्बाब्वे 144वें स्थान पर है और इसमें -1.481 की बड़ी गिरावट आई है. यहां लंबे समय से आर्थिक अस्थिरता और मुद्रा की समस्या बनी हुई है. रोजमर्रा की जिंदगी अनिश्चित रहती है और रोजगार की भी कमी है. बोत्सवाना 143वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 3.464 है और -0.506 की गिरावट आई है. इसे आम तौर पर स्थिर देश माना जाता है, लेकिन अब यहां भी असमानता और आर्थिक बदलाव के संकेत दिख रहे हैं.

मिडिल ईस्ट देशों की रैंकिंग

यमन 142वें स्थान पर है और उसका स्कोर 3.532 है, जिसमें -0.522 की गिरावट आई है. यहां लंबे समय से संघर्ष और मानवीय संकट चल रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है. लेबनान 141वें स्थान पर है और उसका स्कोर 3.723 है, जिसमें -1.208 की गिरावट आई है. यहां आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और लोगों में असंतोष बढ़ा है. रोजमर्रा की सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं.

शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज फटने से 2 लोगों की मौत

नई दिल्ली। निर्मल जिले के महालक्ष्मीवाड़ा इलाके में एक दर्दनाक हादसे में फ्रिज फटने से 2 लोगों की मौत हो गई. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और गर्मियों में घरेलू उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ा दी है. महालक्ष्मीवाड़ा क्षेत्र में रविवार (5 अप्रैल) को एक दुखद हादसा सामने आया, जहां एक घर में रखा फ्रिज अचानक फट गया. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह विस्फोट हुआ, जिसके बाद घर में तेजी से आग फैल गई. इस हादसे में विजय नाम के व्यक्ति और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना अचानक हुई. इसी कारण घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. फ्रिज के फटने के साथ ही तेज धमाका हुआ और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया. आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी.।

हैदराबाद को लखनऊ ने रौंदा

ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में दिलाई जीत

ने 27 गेंद में 45 रन बनाए. उनके बल्ले से 6 चौके और दो छक्के निकले. इससे पहले गेंदबाजी में शमी ने कहर बरपाया था. शमी ने 18 डॉट गेंद फेंकी. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट चटकाए.

लखनऊ ने गेंदबाजी काफी टाइट की थी, और हैदराबाद जैसी मजबूत टीम को 156 रनों पर रोक लिया था. इसके बाद एडेन मार्करम ने तूफानी शुरुआत दिलाई. लास्ट 12 गेंद में लखनऊ को जीत के लिए सिर्फ 13 रन बनाने थे, लेकिन 19वें ओवर में हर्ष दुबे ने सिर्फ 4 रन दिए. अब लखनऊ को लास्ट ओवर में 9 रन बनाने थे. ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर चौका लगाया. अब पांच गेंद में पांच रन बचे. फिर पंत ने चौका लगाया. इसके बाद दो गेंद डॉट हुईं और फिर पंत ने चौका लगाकर जीत दिलाई. 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत अच्छी नहीं रही. मिचेल मार्श 12 गेंद में दो चौके लगाकर 14 रन पर आउट हो गए।

नई दिल्ली। मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी और ऋषभ पंत व एडेन मार्करम की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया है. इसके साथ ही लखनऊ ने अपनी जीत का खाता खोला. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले खेलने के बाद 156 रन बनाए थे. जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा किया. लखनऊ के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने नाबाद 68 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. ओपनर एडेन मार्करम

4 ओवर में सबसे कम रन देने वाले गेंदबाज बने शमी

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेल रहे हैं. टूर्नामेंट का 10वां लीग मैच सनराइजर्स हैदराबाद (SHR) और लखनऊ के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच में शमी ने इतिहास रचते हुए वो काम कर दिया, जो अब तक कोई दूसरा गेंदबाज नहीं कर सका था. शमी ने 4 ओवर में 2.20 की इकॉनमी से सिर्फ 09 रन खर्चे. इसके साथ उन्होंने 2 विकेट भी अपनी झोली में डाले. इस आंकड़े के साथ शमी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 4 ओवर के स्पेल में सबसे कम रन खर्च करने वाले गेंदबाज बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रुणाल पांड्या के नाम पर दर्ज था. 2022 के सीजन में क्रुणाल ने 4 ओवर के स्पेल में 2.75 की इकॉनमी से 11 रन खर्च किए थे.

लखनऊ के लिए सबसे इकोनॉमिकल स्पेल

- 2/9 - मोहम्मद शमी बनाम हैदराबाद, हैदराबाद, 2026 (2.20 इकॉनमी)
- 2/11 - क्रुणाल पंड्या बनाम पंजाब, पुणे, 2022 (2.75 इकॉनमी)
- 3/11 - क्रुणाल पंड्या बनाम गुजरात, लखनऊ, 2024 (2.75 इकॉनमी).

पिछली सीजन थे SRH का हिस्सा

शमी पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे. उनके लिए 2025 का सीजन बहुत खराब रहा था. उन्होंने 9 मैचों की 9 पारियों में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 विकेट चटकाए थे. इस दौरान शमी ने 11.23 की इकॉनमी से रन खर्च किए थे. खराब प्रदर्शन के चलते टीम ने ट्रेड डील के जरिए शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स में भेज दिया था. यह एक ऑल-कैश डील थी. अब शमी ने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ ही कहर बरपाते हुए रिकॉर्ड कायम कर दिया. इससे पहले दिल्ली के खिलाफ खेले गए मैच में शमी ने 4 ओवर में 28 रन खर्च कर 1 विकेट अपने नाम किया था. बात करें शमी के आईपीएल करियर की, तो अब तक उन्होंने 121 मुकाबले खेल लिए हैं।

अशोक शर्मा ने फेंकी आईपीएल 2026 की सबसे तेज गेंद

नई दिल्ली। भारत में भी फास्ट-बॉलिंग का टैलेंट निर कर सामने आ रहा है. इसका सबसे नया उदाहरण अशोक शर्मा हैं, जिन्होंने 154.2 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर सबको चौंका दिया. अशोक शर्मा गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं और सीजन की सबसे तेज गेंद फेंकने का कारनामा उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में किया.

उससे पहले भी उन्होंने दो गेंद 150 किमी प्रतिघंटा से ज्यादा रफ्तार से फेंकी थीं. आखिर अशोक शर्मा हैं कौन, जो अपनी घातक स्पीड के चलते रातों-रात स्टार बन गए हैं. अशोक शर्मा की उम्र अभी महज 23 साल है और वो राजस्थान से आते हैं. अशोक डोमेस्टिक क्रिकेट में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में होगी एंट्री, उम्र का नियम नहीं बनेगा बाधा

नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट क्रिकेट अभी ट्रांजिशन दौर में है, क्योंकि रोहित, कोहली, आश्विन आदि सीनियर्स प्लेयर्स इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं. बीसीसीआई भी टेस्ट के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है. बोर्ड बुनियादी चीजों को ठीक करना चाहता है, ताकि अच्छे नतीजे आएं. इस प्लान में वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं, जो हाल ही में 15 साल के हुए हैं. आईपीएल में तूफानी पारी से चर्चा में आए वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 और डोमेस्टिक में भी प्रभावित किया है. उन्हें टीम इंडिया में शामिल करने की मांग उठ रही है. वैभव के आलावा आयुष म्हात्रे, समीर रिजवी आदि प्लेयर्स भी हैं, जिनको तैयार करने के लिए बीसीसीआई ने

खास प्लान बनाया है. इसका नेतृत्व बीसीसीआई का सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस कर रहा है. पीटीआई की खबर के अनुसार, बीसीसीआई जून-जुलाई में 4 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें 64 प्लेयर्स खेलेंगे. 25 साल से कम के प्लेयर्स इसमें खेलेंगे और टूर्नामेंट के मैच अलग-अलग पिचों पर होंगे. इसका मकसद खिलाड़ियों की तकनीक, क्षमता और धैर्य को परखना है.बीसीसीआई इस टूर्नामेंट के जरिए अगले 10 साल के लिए टेस्ट टीम का मजबूत पूल तैयार करना चाहता है. इसमें 25 प्लेयर्स रणजी और घरेलू सर्किट से चुने जाएंगे, 25 जूनियर क्रिकेट (सीके नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी) से चुने जाएंगे।

अब एक साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रैच्युटी

नई दिल्ली। नए लेबर कोड के तहत ग्रेच्युटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. इसके तहत, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों (FTE) को ग्रैच्युटी पाने के लिए अब पांच साल तक का इंतजार नहीं करना होगा. नियमों में बदलाव के चलते केवल एक साल की निरंतर सर्विस के बाद ही ये ग्रैच्युटी पाने के हकदार होंगे. पहले कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट पर किसी कर्मचारी को काम पर रखती थी, तो उसे स्थायी या परमानेंट कर्मचारियों जैसे लाभ नहीं मिलते थे. अब 'फिक्स्ड-टर्म' के तहत एक तय समय (1 साल या 2 साल) के लिए लिखित कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारी सीधे कंपनी के पेरोल पर रखे जाएंगे. यानी उनकी सैलरी, छुट्टियां और अलाउंस स्थायी कर्मचारियों के जैसे ही मिलेंगे. मौजूदा कानून

(Payment of Gratuity Act, 1972) के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी को ग्रैच्युटी तभी मिलती है, जब वह 5 साल तक की सर्विस पूरी कर लेता है. FTE के तहत, अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ 1 साल 3 महीने का है, तो आपको पूरे 15 महीनों की ग्रैच्युटी मिलेगी. यह उन लोगों के लिए खुशी की बात है, जो खासतौर पर प्रोजेक्ट-बेस्ड काम करते हैं.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश

जंग के बीच भारत ने 7 साल बाद ईरान से खरीदा तेल

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सप्लाई बाधित होने के बीच भारत ने ईरान से फिर तेल खरीदना शुरू कर दिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार (4 अप्रैल 2026) को इसकी जानकारी दी. भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है, उसने मई 2019 के बाद पहली बार ईरान से तेल खरीदा है. उस समय अमेरिका के दबाव के कारण भारत ने ईरानी तेल लेना बंद कर दिया था.

मंत्रालय ने बताया कि मिडिल ईस्ट में सप्लाई में आई दिक्कतों को देखते हुए भारतीय रिफाइनरियों ने अपनी जरूरत का कच्चा तेल सुरक्षित कर लिया है, जिसमें ईरान से खरीदा गया तेल भी शामिल है. साथ ही यह भी कहा गया कि ईरान से तेल खरीदने में भुगतान से जुड़ी कोई समस्या नहीं है. पिछले महीने अमेरिका ने सप्लाई की कमी को देखते हुए ईरान के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे कुछ प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया था. इसके बाद भारत के लिए ईरान से तेल खरीदना आसान हो गया.

कंपनियों को भारत सरकार की छूट

सरकार के अनुसार, आने वाले महीनों के लिए भारत ने अपनी पूरी जरूरत का कच्चा तेल सुनिश्चित कर लिया है. भारत 40 से ज्यादा देशों से तेल आयात करता है और कंपनियों को यह छूट है कि वे अपनी जरूरत और कीमत के हिसाब से कहीं से भी तेल खरीद सकती हैं. इसके अलावा भारत ने ईरान से 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी भी खरीदी है. यह गैस एक ऐसे जहाज से लाई गई है जिस पर पहले प्रतिबंध लगे थे. यह जहाज बुधवार को कर्नाटक के मंगलुरु बंदरगाह पर पहुंचा और वहां गैस उतारी जा रही है. इस फैसले को मौजूदा हालात में भारत के लिए ईंधन सप्लाई बनाए रखने के अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है.

जीएसटी कलेक्शन पहली बार ₹2 लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर चल रही अनिश्चितता के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. मार्च 2026 में सकल माल एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन में 9 फीसदी की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है. इस उछाल के साथ ही मासिक राजस्व 2 लाख करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया है. वित्त वर्ष 2025-26 में यह तीसरा मौका है, जब कलेक्शन इस स्तर पर पहुंचा है.ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में कुल जीएसटी कलेक्शन ₹2,00,344 करोड़ रहा. इस वृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका आयात की रही, जिससे प्राप्त राजस्व 17.8 प्रतिशत बढ़कर 53,861 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, घरेलू मोर्चे पर भी 5.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिला. दिलचस्प बात यह है कि सरकार द्वारा सितंबर 2025 में जीएसटी दरों में बड़े बदलाव किए गए थे।

साप्ताहिक शहर सत्ता

कांग्रेस बोली-बस्तर के हर गांव को 1 करोड़ दे सरकार

सरकार ने खुद घोषणा की थी, जो गांव नक्सल मुक्त होंगे, उन्हें 1 करोड़ देंगे

शहर सत्ता/रायपुर। बस्तर के विकास को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। पार्टी ने कहा कि, सरकार अपने वादे के मुताबिक बस्तर के हर ग्राम पंचायत को तत्काल 1 करोड़ रुपए की राशि जारी करे। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि, सरकार ने खुद घोषणा की थी कि जो गांव नक्सल मुक्त होंगे, उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब जब सरकार के स्तर पर बस्तर सहित पूरे प्रदेश को नक्सल मुक्त बताया जा रहा है, तो इस घोषणा को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

विशेष पैकेज और रोजगार की मांग

कांग्रेस ने "डबल इंजन" सरकार से बस्तर के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इससे क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। साथ ही बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने, वनोपज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत बताई गई है।

NMDC मुख्यालय बस्तर में खोलने की मांग

कांग्रेस ने NMDC Limited का मुख्यालय बस्तर में स्थापित करने की मांग भी उठाई है। पार्टी का कहना है कि बस्तर से निकलने वाले लौह अयस्क से कंपनी को लाभ होता है, लेकिन मुख्यालय हैदराबाद में है। कांग्रेस के अनुसार, पहले परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण यह व्यवस्था समझ में आती थी, लेकिन अब बस्तर में बुनियादी सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं, ऐसे में मुख्यालय यहां शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके।

खनिज संपदा और निजीकरण पर चिंता

कांग्रेस ने यह भी कहा कि, बस्तर के लोगों में आशंका है कि क्षेत्र की खनिज संपदा और जंगल निजी उद्योगपतियों को सौंपे जा सकते हैं। पार्टी ने सरकार से स्पष्ट गारंटी देने की मांग की है कि बस्तर के संसाधनों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा।

रेल कनेक्टिविटी पर भी सवाल

पार्टी ने बस्तर की रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने की मांग की है। कांग्रेस ने दल्लीराजहरा-जगदलपुर रेल लाइन परियोजना में देरी पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि, इस परियोजना की घोषणा 2017-18 में की गई थी और 2021 तक इसे पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे बस्तर के लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका।

अर्बन नक्सलवाद पर गृहमंत्री विजय शर्मा से सवाल का मिला ये जवाब !

अर्बन नक्सल पर क्या कार्रवाई हुई है? गृहमंत्री बोले- उस दिशा में अभी कोई काम है नहीं और कहा नहीं जा सकता

शहर सत्ता/रायपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा रविवार को दुर्ग जिले में थे। इस दौरान उन्होंने अर्बन नक्सलवाद के सवालों के जवाब में कहा कि अब तक सरकार की एक ही बात थी और वो ये थी कि हथियार छोड़ दें, भारत का संविधान हाथ में रखें और भारत के संविधान के अनुरूप जो करना है वो करें। तो इसमें उस दिशा में अभी कोई काम है नहीं और कहा नहीं जा सकता।

गृह मंत्री विजय शर्मा दुर्ग के पाटन क्षेत्र स्थित चन्द्राकर भवन, जामगांव (एम) पहुंचे, जहां उन्होंने चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज, दुर्ग राज के 56वें वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नक्सलवाद, सीएएफ वेटिंग अभ्यर्थियों के अलावा बंगाल चुनाव पर भी बात की। नक्सल मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर के गांवों में पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क और मोबाइल टावर जैसी सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन अब सरकार इन सभी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर काम कर रही है। अर्बन नक्सल के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि हथियार छोड़कर संविधान के रास्ते पर चलें, उसी दिशा में काम होना चाहिए।

अभी सुरक्षा बलों को नहीं हटाया जाएगा

नक्सल उन्मूलन के बाद फोर्स वापसी के सवाल पर विजय शर्मा ने कहा कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी अभी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैसे ऑपरेशन के बाद तुरंत डॉक्टर को हटाना ठीक नहीं होता, उसी तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभी एहतियात जरूरी है। उन्होंने कहा कि आईईडी कौन निकालेगा? हम लोग जाकर निकालेंगे कि फोर्स निकालेगी? उसकी टेक्नोलॉजी है, उस पर फोर्स काम करती है। अभी प्रतिदिन यही काम चल रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे नक्सल मुक्त गांव की तरह आईईडी फ्री विलेज बना दें वहां पर।

गृह मंत्री विजय शर्मा को काला झंडा दिखाने के पहले युकां जिला अध्यक्ष प्रांजल तिवारी गिरफ्तार

शहर सत्ता/बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में पुलिस ने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रांजल तिवारी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि, अध्यक्ष प्रांजल तिवारी द्वारा गृह मंत्री विजय शर्मा को काला झंडा दिखाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, शहर में युवा कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही थी, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए प्रांजल तिवारी को बेमेतरा से हिरासत में लिया। वहीं अध्यक्ष प्रांजल तिवारी के समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है और वे इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं। हालांकि, पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कदम केवल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उठाया गया है।

इलाके में भारी पुलिसबल तैनात

गृह मंत्री विजय शर्मा के संभावित दौरे को देखते हुए प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संगठन विरोध प्रदर्शन के दौरान काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज कराने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

बीजेपी बोली- पंचायत से लेकर पार्षद तक की मिलीभगत, पुलिस और प्रशासन तक पहुंचा मामला

कांग्रेस पदाधिकारियों पर सरकारी-जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के आरोप,जांच शुरू

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के आरंग इलाके में सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आया है। आरोप कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारियों पर लगे हैं, जिन पर पंचायत स्तर से जमीन का पट्टा बनाकर उसे अपने लोगों के नाम कराने का आरोप है। मामले की शिकायत मंदिरहसौद थाना क्षेत्र में की गई है और प्रशासनिक जांच शुरू हो चुकी है।

क्या है पूरा मामला?

आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोढ़ी में सरकारी जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। आरोप है कि पंचायत के प्रस्ताव के जरिए शासकीय जमीन को निजी नामों पर दर्ज कर दिया गया और बाद में उसकी खरीदी-बिक्री भी की गई। बीजेपी का दावा है कि इस पूरे मामले में पंचायत के तत्कालीन सचिव, सरपंच और उपसरपंच की भूमिका संदिग्ध है और उन्होंने जमीन का अवैध आवंटन किया।

इन पर लगे आरोप

बीजेपी प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कण्डेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच गोपाल धीवर, जो अभी कांग्रेस के सेक्टर प्रभारी हैं, ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि गोपाल धीवर ने अपनी पत्नी, जो जनपद सदस्य हैं, के जरिए जमीन से जुड़ा प्रस्ताव पास करवाया। आरोप है कि प्रगति मिश्रा के नाम करीब 4 एकड़ सरकारी जमीन दर्ज कर दी गई। साथ ही, कांग्रेस पार्षद अनुज मिश्रा को 20 साल से कब्जा दिखाकर जमीन आवंटित कर दी गई। इसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी प्रवीण सिंह पर भी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया है।

कैसे हुआ कथित खेल?

आरोप है कि सरकारी जमीन पर पहले कागजों में कब्जा दिखाया गया, फिर पंचायत से प्रस्ताव पास कराकर पट्टा जारी किया गया। इसके बाद उसी जमीन की खरीदी-बिक्री की गई, जो नियमों के खिलाफ है।

जांच और शिकायत की स्थिति

मामले की शिकायत मंदिरहसौद थाना में दर्ज कराई गई है। जांच जारी है, लेकिन अब तक किसी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी का आरोप है कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें से कुछ फरार भी बताए जा रहे हैं।

दिव्यांग मिलाप और बंसी को मिली नई राह मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल से बने आत्मनिर्भर

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टर कक्ष में ग्राम भानसोज, विकासखंड आरंग के मिलाप दास मानिकपुरी एवं ग्राम छटेरा, विकासखंड आरंग के बंशी लाल साहू को मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल प्रदान की। दोनों हितग्राही 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं और लंबे समय से दैनिक कार्यों एवं आवागमन में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। कलेक्टर डॉ. सिंह के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत दोनों हितग्राहियों को बैटरी चालित ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराई गई। ट्रायसाइकिल प्राप्त होने के बाद श्री मानिकपुरी एवं श्री साहू ने कहा कि, "अब वे अपने रोजमर्रा के काम खुद कर सकते हैं। पहले जहां उन्हें कहीं जाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब वे स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ-जा सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ा है।"

रायल्टी चोरी करने किया चूना पत्थर का अवैध भंडारण, 5 खदान-क्रेशर में छापा

रायपुर। रायपुर जिले के मंदिर हसौद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनसुली में बड़े पैमाने पर चूना पत्थरों का कारोबार अवैध रूप से हो रहा है। इसका खुलासा खनिज विभाग द्वारा चार दिनों के भीतर की गई कार्रवाई से हुआ है। विभागीय टीम ने शनिवार को ग्राम धनसुली में संचालित 5 खदानों में छापा मारकर जांच पड़ताल की। इस दौरान खदानों को संचालित करने वाले पट्टेदार से लेकर कर्मचारी सभी भाग खड़े हुए, क्योंकि इन खदानों में कुछ में तो अवैध रूप से खनन और क्रेशर का काम चल रहा था, वहीं जिन खदानों के लिए अनुबंध हुआ है, वहां भी भारी मात्रा में स्वीकृत क्षमता से अधिक भंडारण तथा अवैध भंडारण मिला है। इन सभी खदानों का संचालन करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है, साथ ही 4 क्रेशर को सील किया है। खनिज विभाग के जिला अधिकारी राजेश मालवे ने बताया कि कलेक्टर के सख्त निर्देश हैं कि प्रत्येक खदान की जांच की जाए और जहां भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, या अवैध रूप से संचालन, खनन, भंडारण एवं परिवहन किया जा रहा है, उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करें।

कलेक्टर के इस निर्देश के तहत शनिवार को सहायक खनिज अधिकारी उमेश भार्गव के नेतृत्व में खनिज विभाग के टीम को तहसील खरोरा अंतर्गत ग्राम धनसुली एवं मुरा में चूना पत्थर की खदानों की जांच के लिए भेजा गया था। इस जांच में क्षेत्र के तहसीलदार भी थे। जांच के दौरान ग्राम धनसुली में बारी-बारी से श्रीमहालक्ष्मी लाइम स्टोन जितेंद्र अग्रवाल, आशापुरा स्टोन क्वारी बाड़ीलाल पटेल, राजेश भवनानी एवं आशीष अग्रवाल खदान के अलावा ग्राम मुरा स्थित श्रीराम इंटरप्राइजेज प्रकाश आडवाणी के यहां जांच की गई। इस जांच में कहीं अवैध रूप से खनन, क्रेशर का भंडारण मिला, तो कहीं नियमों के विरुद्ध भंडारण के साथ भारी मात्रा में अवैध भंडारण पाया गया। इसके तहत खदान और क्रेशर का संचालन कराने वाले सभी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 4 क्रेशर मशीन को सील भी किया है।

3 दिन पूर्व 6 खदानों पर हुई कार्रवाई

खनिज विभाग ने इस कार्रवाई से 3 दिन पूर्व धनसुली, नरदहा एवं खपरी में भी आधा दर्जन चूना पत्थर खदानों की जांच की थी। सभी खदानों में नियमों के विरुद्ध खनन, क्रेशर का भंडारण होना पाया। इसके तहत इनमें से 4 खदानों में लगी क्रेशर मशीनों को सील करने की कार्रवाई भी की गई, वहीं अन्य 2 खदानों के पट्टेदारों को नोटिस जारी किया। इन खदानों में अनुबंध से अधिक रकबा में खनन, सूचक बोर्ड नहीं लगाना, रायल्टी सहित अन्य कई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

करोड़ों रुपए की रायल्टी चोरी

विभाग ने चार दिन में की गई इस कार्रवाई से करोड़ों रुपए की रायल्टी चोरी का खुलासा हुआ है। इन सभी खदानों केशर में अवैध भंडारण से स्पष्ट हो गया कि इनका संचालन करने वाले लोग रायल्टी बचाने के लिए अवैध रूप से तथा अतिरिक्त रकबा में चूना पत्थर का खनन एवं भंडारण कराकर करोड़ों रुपए की रायल्टी बचाकर शासन को चूना लगा रहे हैं।

कलेक्टर गौरव सिंह के प्रयासों से बच्चों के सर्वांगीण विकास की राह प्रशस्त

कला केंद्र रायपुर में संगीत, तबला, हारमोनियम सहित 24 विधाएं सीखने का अवसर

शहर सत्ता/रायपुर। शहर के प्रतिष्ठित संस्थान कला केंद्र रायपुर द्वारा "समर कैंप 2026" का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को रचनात्मक, उपयोगी और ज्ञानवर्धक बनाना है। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर कला केंद्र में समर कैंप के माध्यम से बच्चों को संगीत, नृत्य, चित्रकला, योग, शतरंज एवं स्पोकन इंग्लिश जैसी विविध गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे बच्चों की प्रतिभा निखरेगी और उनमें आत्मविश्वास के साथ-साथ रचनात्मक सोच का विकास होगा।

यह कैंप तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, दूसरा चरण 01 मई से 15 मई तथा तीसरा चरण 16 मई से 30 मई तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। कैंप में भाग लेने के लिए पंजीयन शुल्क 110 रुपए तथा प्रशिक्षण शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है। सीमित सीटों के कारण अभिभावकों से अपने बच्चों का पंजीयन शीघ्र कराने की अपील की गई है। यह समर कैंप जी.ई. रोड स्थित इंटरनेशनल स्विमिंग पूल के पीछे स्थित कला केंद्र परिसर में आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी एवं पंजीयन के लिए इच्छुक अभिभावक 9109029034 एवं 9669039034 पर संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप जिलेवासियों को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कला केंद्र रायपुर की शुरुआत की गई है। यह केंद्र बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु वर्ग के लिए एक सशक्त मंच बनकर उभरा है, जहां संगीत, तबला, हारमोनियम सहित 24 विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

जिले में राजस्व पखवाड़ा के तहत शिविरों से मिली राहत

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशन में जिले में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आरंग एवं धरसीवां, अभनपुर तहसील के विभिन्न ग्रामों में राजस्व शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में भैंसा, तुलसी, अमसेना, बाना, गुमा, गुल्लू, परसतराई, गिधौरी, कुकेरा, अकोली, मनोहरा, देवरी, चरौदा, रवेली, नेउरडीह, कुकरा, जरौड, गिधौरी, अकोली, सहित अन्य ग्रामों के ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं दर्ज कराईं।

शिविर के दौरान नक्शा बटांकन, बी-1, खसरा संबंधित प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया। साथ ही आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि लोक सेवा केंद्र के माध्यम से की गई, ताकि निर्धारित समय-सीमा में उनका शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

- **राजस्व शिविरों में नक्शा, खसरा व प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों का त्वरित निपटारा**

जिला पंचायत सीईओ ने ली प्रधानमंत्री राहत योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय बैठक

अब दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज

शहर सत्ता/रायपुर। प्रधानमंत्री राहत योजना (PM RAHAT) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन की अध्यक्षता एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. सार्थक नंदा ने प्रधानमंत्री राहत योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक राष्ट्रीय कैशलेस आपातकालीन उपचार योजना है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह योजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित एवं निशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग एवं शहरी सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को लाभ दिया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि दुर्घटना की स्थिति में 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से पीड़ित को नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर तुरंत उपचार प्रारंभ किया जा सकता है तथा संबंधित अस्पताल को योजना के तहत उपचार की जानकारी देना आवश्यक होगा। बैठक में उपस्थित निजी अस्पतालों से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सहयोग करने, पात्र मरीजों को लाभ दिलाने एवं जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई।

यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराकर उनके जीवन की रक्षा करने एवं आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के राज्य अध्यक्ष डॉ. अनूप वर्मा, निजी अस्पताल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. शुक्ला, IMA के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता, फोगसी की अध्यक्ष डॉ. मोनिका पाठक, फोगसी के सचिव एवं अन्य सदस्य सहित जिले के निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रामायण के टीजर से शुरू हुआ इंडियन सिनेमा का मिशन इंटरनेशनल!

नमित मल्होत्रा की रामायण का टीजर सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में खूब चर्चा बटोर रहा है. रणबीर कपूर के राम हों या शानदार स्केल और स्पेशल इफेक्ट्स... रामायण के टीजर ने ये झलक दिखा दी है कि ये कहानी भारतीय संस्कृति से जरूर निकल रही है, मगर इसका टारगेट इंटरनेशनल ऑडियंस है. हॉलीवुड में लंबे समय से एक्टिव नमित मल्होत्रा कई बड़ी इंटरनेशनल फिल्मों के लिए ऑस्कर जीत चुके हैं. रामायण को नमित इस एम्बिशन के साथ तैयार कर रहे हैं कि भारत की संस्कृति से जुड़ी एक कहानी ग्लोबल ऑडियंस को दिखानी है. इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को साधने चले नमित का पहला कदम रामायण का टीजर है. मगर इंडियन कहानियों को इंडियन सिनेमा के स्टाइल में इंटरनेशनल सिनेमा तक पहुंचाने की नीयत 2026 में भारतीय सिनेमा की थीम बनने जा रही है. रामायण के साथ ही और भी कई बड़े प्रोजेक्ट इसी थीम पर बन रहे हैं.

टॉक्सिक

KGF स्टार यश ने अपनी अगली फिल्म को इंटरनेशनल स्केल देने के लिए डायरेक्टर गीतू मोहनदास से हाथ मिलाया है. टॉक्सिक के टीजर से ही सामने आ चुका है कि इस गैंगस्टर कहानी को ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन के लेवल पर इंटरनेशनल ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए बनाया जा रहा है. इसका एक्शन और विजुअल्स काफी हाई कॉन्सेप्ट हैं. मेकर्स का प्लान इसे इंग्लिश और कुछ यूरोपियन भाषाओं में रिलीज करने का है. ओवरसीज में रिलीज के लिए टॉक्सिक के मेकर्स ने बड़ी इंटरनेशनल कंपनी Fars Films से हाथ मिलाया है. यश की ये फिल्म 4 जून 2026 को आ रही है.

किंग

King की सबसे बड़ी इंटरनेशनल अपील खुद Shah Rukh Khan हैं. इस फिल्म का एक्शन, स्टंट्स और विजुअल्स इंटरनेशनल ऑडियंस के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि शाहरुख अपने इस एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं कि वो इंडियन फिल्म के साथ विदेशी दर्शकों को भी थिएटर्स तक ला सकें.

स्पिरिट

अगर किंग के पास शाहरुख खान हैं, तो Spirit में Prabhas हैं. Baahubali 2: The Conclusion के बाद से इंटरनेशनल ऑडियंस प्रभास पर नजर रखती आई है. स्पिरिट में हॉलीवुड एक्टर Don Lee विलेन के रोल में हैं. मेकर्स इसे 5 भारतीय भाषाओं के अलावा चाइनीज, कोरियन और जापानी भाषा में रिलीज करना चाहते हैं. इसके डायरेक्टर Sandeep Reddy Vanga बोल चुके हैं कि वो कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं कि हॉलीवुड देखता रह जाएगा. स्पिरिट 5 मार्च 2027 को रिलीज होनी है.

कोविड के बाद 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती एक्ट्रेस हैं रश्मिका

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में धाक जमा चुकीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपने बर्थडे के मौके पर अपकमिंग फिल्म 'मायसा' से नया लुक जारी किया गया है, जिसमें उनका लुक देखते ही बन रहा है. कोविड-19 के बाद से वो इकलौती अभिनेत्री हैं, जिन्होंने बैक टू बैक हिट्स दी और 3 फिल्मों से तो उन्होंने हैट्रिक ही मार दी और वह 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती अभिनेत्री बन चुकी हैं.

कोविड-19 के दौर में जहां बॉलीवुड में कोई भी फिल्म रिलीज हो रही थी तो उसे फ्लॉप का सामना करना पड़ रहा था लेकिन उसी बीच दो फिल्में रिलीज की गईं पहली 'पुष्पा द राइज' और दूसरी 'केजीएफ 2' तो दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था. 'पुष्पा' ने 2021 में अकेले घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ और वर्ल्डवाइड 300 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. इस फिल्म के बाद रश्मिका नेशनल क्रश बन गईं. अल्लू अर्जुन और रश्मिका की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था.

3 ब्लॉकबस्टर से लगाई हैट्रिक

'पुष्पा द राइज' के बाद रश्मिका मंदाना लाइमलाइट में आ गईं और फिर इसके सीक्वल का लोगों के इंतजार होने लगा. 2022 में 'सीता रामम' से भी सभी का ध्यान खींच लिया. इसके बाद एक्ट्रेस की झोली में कई फिल्में आईं और उन्होंने महज 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों से ही हैट्रिक मार दी. वह कोविड 19 के बाद 3000 करोड़ कमाने वाली इकलौती एक्ट्रेस बन गईं. रश्मिका मंदाना ने 'सीता रामम' के बाद फिल्म 'एनिमल' (2023) में काम किया और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 915 करोड़ का कलेक्शन दुनियाभर में किया. इसके बाद वह 'पुष्पा द रूल' (2024-25) में नजर आईं. इसने तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दुनियाभर में 1742 करोड़ का बिजनेस किया. अभी इसका क्रेज कम हो पाता कि इसके बाद सिनेमाघरों में आई 'छावा' (2025). इसने दुनियाभर में 807 करोड़ कमाए.

अश्लील साइट पर डाल दी गई थीं जाह्नवी कपूर की मॉर्फ्ड फोटोज

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात करती हैं. हाल ही में उन्होंने डीपफेक्स को लेकर बात की. साथ ही उन्होंने अपने साथ स्कूल में हुई एक डिस्टर्बिंग घटना के बारे में भी बताया. राज शमानी के पॉडकास्ट में जाह्नवी ने कहा, 'मुझे नहीं पता इसे टेक्निकली डीपफेक कहेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसा ही था. मैंने अपनी फोटोज अश्लील साइट पर देखी थी. हमारी आईटी क्लास थी स्कूल में. लड़के उन साइट्स पर जाते थे फन के लिए और मेरी फोटोज वहां थीं. मैं उस वक्त 15 साल की थीं. ये बहुत खराब एक्सपीरियंस था.'आगे उन्होंने कहा, 'एक प्वॉइंट पर, मुझे लगा क्यो? क्या ये वो कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है? जैसे कि इन चीज़ों में कोई नैतिकता ही न हो. सोशल मीडिया पर सब अपनी बातें रख रहे हैं. अब नैतिकता के मामले में बिहेवियर थोड़ा-बहुत सुधरा है लेकिन बड़े पैमाने पर ये अभी भी समस्या है. बहुत से लोगों को ये नॉर्मल लगता है. आप एक पब्लिक फिगर हैं, इसलिए ऐसा होगा ही.'

AI जेनरेटेड फोटोज पर क्या बोलीं जाह्नवी?

जाह्नवी ने AI जेनरेटेड फोटोज को लेकर भी कहा, 'इससे मैं शांति में नहीं हूं. मेरे कई ऐसे विजुअल्स हैं, यहां तक कि ऑफिशियल न्यूज़ पेजेस पर भी सर्कुलेट हुए हैं जो पूरी तरह से AI से बने हैं. मैंने कभी वो चीजें नहीं पहनी, मैंने कभी वैसे फोटोज नहीं क्लिक करवाए. लेकिन वो ऐसे सर्कुलेट हुए जैसे वो रियल हैं.' जाह्नवी कपूर ने फिल्म धड़क से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. वो बवाल, मिली, गुड लक जैरी, रूही, उलझ, परम सुंदरी जैसी फिल्मों में दिखीं. पिछली बार उन्हें सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में देखा गया. अब वो पेड्डी में दिखेंगी. इस फिल्म में वो राम चरण के अपोजिट नजर आएंगी. फिल्म को लेकर काफी चर्चा है.

ओटीटी पर छाई 15 साल पुरानी वेब सीरीज

कुछ फिल्में और सीरीज़ ऐसी होती हैं, जो रिलीज़ हुए सालों बाद भी दर्शकों और फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती हैं. उनकी कहानी, किरदार और खास पलों का जादू समय के साथ फीका नहीं पड़ता. आज हम आपको एक ऐसी ही सीरीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 15 साल पुरानी होने के बावजूद अब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में है. आइए जानते हैं, यह सीरीज़ कहां स्ट्रीम हो रही है.दरअसल, इस सीरीज का नाम है 'गेम ऑफ थ्रोन्स'. इस सीरीज का पहली सीजन साल 2011 में रिलीज हुआ था. ये एक अमेरिकी टीवी सीरीज है, जो George R. R. Martin की किताब A Song of Ice and Fire पर बेस्ड है.बता दें, इस सीरीज के टोटल 8 सीजन रिलीज हो चुके हैं और इसमें टोटल 73 एपिसोड हैं. इस सीरीज में कई कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है. इसके हर एक एपिसोड

उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार है सरहुल

डा. वेदवती मंडावी

सरहूल उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार चैत्र मास में मनाया जाता है। इस पर्व में वे अपने नए जमाई को विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। उरांव इन्हें कुरूख भाषा में खद्दी मन्ना कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ भी सरहुल होता है। सरहुल पूजोत्य से पूर्व तक धरती को अविवाहित कन्या की भांति देखा जाता है। उरांव जनजाति धरती से उत्पन्न नए फल फूलों को घरों में प्रवेश तथा उपयोग नहीं करते। इस नियम का सभी कड़ाई से पालन करते हैं। सरहुल त्योहार के दिन धरती एवं सूर्य के प्रतीकों से विवाह का स्वांग रचाते हैं। इस विवाह में अपने कुल देवता को साक्षी मान कर प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि को कायम रखने के लिए हम दोनों वर और कन्या को उतार रहे हैं। सुख दुख में हमारी रक्षा करना तथा हमारी संतान को आप आशीर्वाद दें, ताकि वह भी हमारी इस परंपरा को कायम रख सकें। गांव के महंतों, पाहन, पनभरा आदि मिल कर धरती पर हड़िया में पेय पदार्थ अर्पित कर दुआ मांगते हैं। मानते हैं कि सूर्य और धरती के परस्पर सहयोग से ही मानव उपयोगी समस्त वस्तुओं का सृजन हुआ है। अतः आदिम जन भी अपनी बुद्धि और समझ के अनुरूप सृजनकर्ता का
अभिनंदन करते हैं और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के लिए याद करते हैं। इस जनजाति द्वारा इस अवसर पर गाए जाने वाला यह गीत -

चिमिन संगीर रे अब
गऊबा सरना
सिंग बोगाय केड़ा तनाय
नेवताबु तनाय तोला
बू से नोगा मियाद बरु फारोम रे
एबाय केड़ा तनाय
अवाय सिंग बोगाए नेवता
तवा दो बू से नोगा।

अर्थात सरना पूजा स्थल कितना दूर है, परम पिता हमें बुला रहे हैं, सिंगबोंगा हमें आमंत्रण दे रहे हैं। चलो आज सब जाएंगे।

छत्तीसगढ़ी लेखन के पहले का दौर

डा. सुधीर शर्मा

राजा महाराजाओं के पुरोहित, जो उत्तर प्रदेश के बनारस व इलाहाबाद की ओर से आए, बिहार के मिथिला अंचल से आए वे ब्रज अवधि में रचना कर राजकुमारों को लेखन में प्रवीण करते रहे। राजा की भाषा, प्रजा की भाषा होती है। लिखना पूर्व में छत्तीसगढ़ी में नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में पूर्व में अनेक कवि हुए, पर वे ब्रज व अवधी में लिखते रहे। 18 वीं शताब्दी में महाकवि खंडेराव भोंसले ने अपने महाकाव्य के दूसरे खंड में ' कृष्ण रुक्मिणी विवाह * प्रसंग में छत्तीसगढ़ी रीति रिवाजों का वर्णन छत्तीसगढ़ी शब्दों के प्रयोग के साथ दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया। इसके बाद 19 वीं सदी में प. सुंदरलाल शर्मा ने खड़ी बोली, अवधी और छत्तीसगढ़ी में लिखना प्रारंभकिए और' छत्तीसगढ़ी दानलीला' जैसा लघु प्रबंध काव्य लिख कर अपार लोकप्रियता प्राप्त करते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया। आगे के क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नद्दष्टा के रूप में, सेना में भी छत्तीसगढ़ रेजिमेंट की कल्पना कर नाट्य सूजन करने वाले डा. खूबचंद बघेल ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए ऊंच नीच, जरनैल सिंह और करम छड़हा नाटक का सूजन किया। तब तक गिरवर दास वैष्णव ने भी सामाजिक कुरीतियों और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी कविताओं के माध्यम से आग उगलना प्रारंभ कर दिया था। प. मुकुटधर पाण्डेय ने कालिदास के मेघदूत का सौष्ठवयुक्त छत्तीसगढ़ी में छंदोबद्ध अनुवाद किया। यह सब छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य रचना का अंकुरण काल था।

अब दिखाई नहीं देते गांवों में कुआं टेंड़ा रहट

डा. नीलकंठ देवगन

हले पीने का पानी का प्रमुख साधन होता था कुओं । जमीन में खोदा गया गहरा गड्ढा जिससे रस्सी बाल्टी के जरिये पानी निकाला जाता था। धंसकने से बचाने दीवाल में पत्थर या ईंट लगा दिया जाता था। हर गांव शहरों में कुएं होते थे। कुएं का पानी शुद्ध, ताजा होता था। अब हर गांव शहरों में चल बोरिंग की सुविधा हो गई है, विद्युत पंप लग गए है। कुओं का उपयोग कम होता गया और अब तो कुएं दिखते नहीं है। पट गये या उन्हें डंक दिया गया। कुजां से पानी निकालने में कसरत हो जाती थी। गगरी, घड़ा या होला सिर पर रखकर लाने से
महिलाओं के शरीर का संतुलन बना रहता था।
टेड़ा कुएं से पानी निकालने का पारंपरिक ग्रामीण पद्धति होती थी। इसमें लंबे बांस के सिरे पर बाल्टी बांधकर एक सहते के माध्यम से पानी ऊपर खींचा जाताथा । सब्जी बड़ी की सिंचाई के लिए इसका उपयोग होता था।
साट कुएं से पानी निकालने और खेतों की सिंचाई करने का पारंपरिक तरीका होता था। इसमें बेलों द्वारा घुमाया जाने वाला लोहे का गोलाकार पहिया होता था जिसमें बाल्टियों या मोटे टीन के डिब्बों की श्रृंखला होती जो कुएं से पानी भरकर खेतों में पहुंचाती। अब कुएं ही नहीं तो टेंड़ा और रहट कहां से होंगे ? यांद कहीं हैं भी तो उनमें मोटर पंप डाल दिये गये हैं।

महिसाधक संप्रदाय के महान आचार्य थे बुद्धघोष

सरयूकांत झा

सिरपुर के बौद्ध विहार में बुद्धघोष निवास करते थे जो महर्षि रैवत के शिष्य थे। वहां से प्राप्त शिलालेख में उनका वर्णन मिलता है। ईसा पूर्व सम्राट अशोक के काल में स्थविर मत का विस्तार हुआ। आचार्य बुद्धघोष इसी मत के मानने वाले इतिहास कार विद्वान थे। इनका जन्म स्थान कोसल ही था। वे मंडला के महिसाधक बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। आचार्य बुद्धघोष वेद वेदांग में पारंगत थे, उनमें विलक्षण तर्क बुद्धि थी। आपने यहां कई ग्रंथों की रचना की जिसमें अट्ठकथा, वाणोंदय, अट्ठसालिनी प्रमुख है। आचार्य बुद्धघोष बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध आधार ग्रंथ त्रिपिटक' के सबसे बड़े अट्ठकथाकार माने जाते हैं। श्रीलंका के राजा महानाम के संरक्षण में उन्होंने बौद्ध धर्म के विशुद्ध मार्ग के आधार पर 'विशुद्धि मग्ग' का पाली भाषा में निर्माण किया। सिंहली भाषा में लिखित सभी अट्ठाकथाओं का पाली भाषा में अनुवाद किया। महान विद्वान आचार्य नरेंद्रदेव ने बुद्धघोष को सिंहली अट्ठकथाओं का सबसे बड़ा व्याख्याकार सिद्ध किया है।' पद्य चूड़ामणि' नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखी गई है।

धार्मिक महत्व के देवालय और गुफा राजपुर कोठी में

आशा ध्रुव

सरगुजा अंचल में राजपुर के दक्षिण दिशा में 3 कि मी दूरी पर गेऊर नदी के तट पर ओफरा गांव के पास एक ऊंचे टीले पर राजपुर कोठी है। यहां प्राचीन काल के देवालय हैं जहां शंभु गौरा के पिंड स्थापित हैं। यहां से लगा लालमाटी ग्राम में एक प्राचीन गढ़ है जहां कनेर नामक गोंड राजा का राज्य था। इसके अलावा आसपास में बेलसर हर्राटोला के केरा कछार में शंभु महादेव का देवालय, चलगली का महामाया देवालय, जोगापाठ के बीहड़ जंगल में प्राकृतिक गुफा, धनपुर में गोंड राजाओं की चांडी देवी और अन्य देवों के देवालय, शिवपुर का शंभु महादेव देवालय, आरा पहाड़ में महादेव मंदिर, पीपरोल पर्वत में महादेव की तपोभूमि, बच्छराज पर्वत में स्थित नागराज का निवास, रंगई जंगल में महादेव गुफा, रमकोला की पिंगलाई देवी सीरीकोट का शंभु देवालय जैसे और भी अनेक प्राचीन स्थल हैं जो इतिहास की दृष्टि से आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी तरह वेनदाई पर्वत के कैमूर श्रृंखला में सोन नदी के किनारे समतल भू भाग पर गोंड राजाओं द्वारा बनाया गया किला है, यहां सात तालाब हैं जहां का पानी कभी नहीं सूखता । इन स्थानों पर समय समय धार्मिक आयोजनों के साथ ही मेले का भी आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोगों के लिए उपरोक्त स्थलों का अपना अलग ही महत्व है।

जनगणना 2026-27 मकानों की गिनती 16 से

सदस्यों की संख्या, मुखिया कौन, सामान भी गिनेंगे

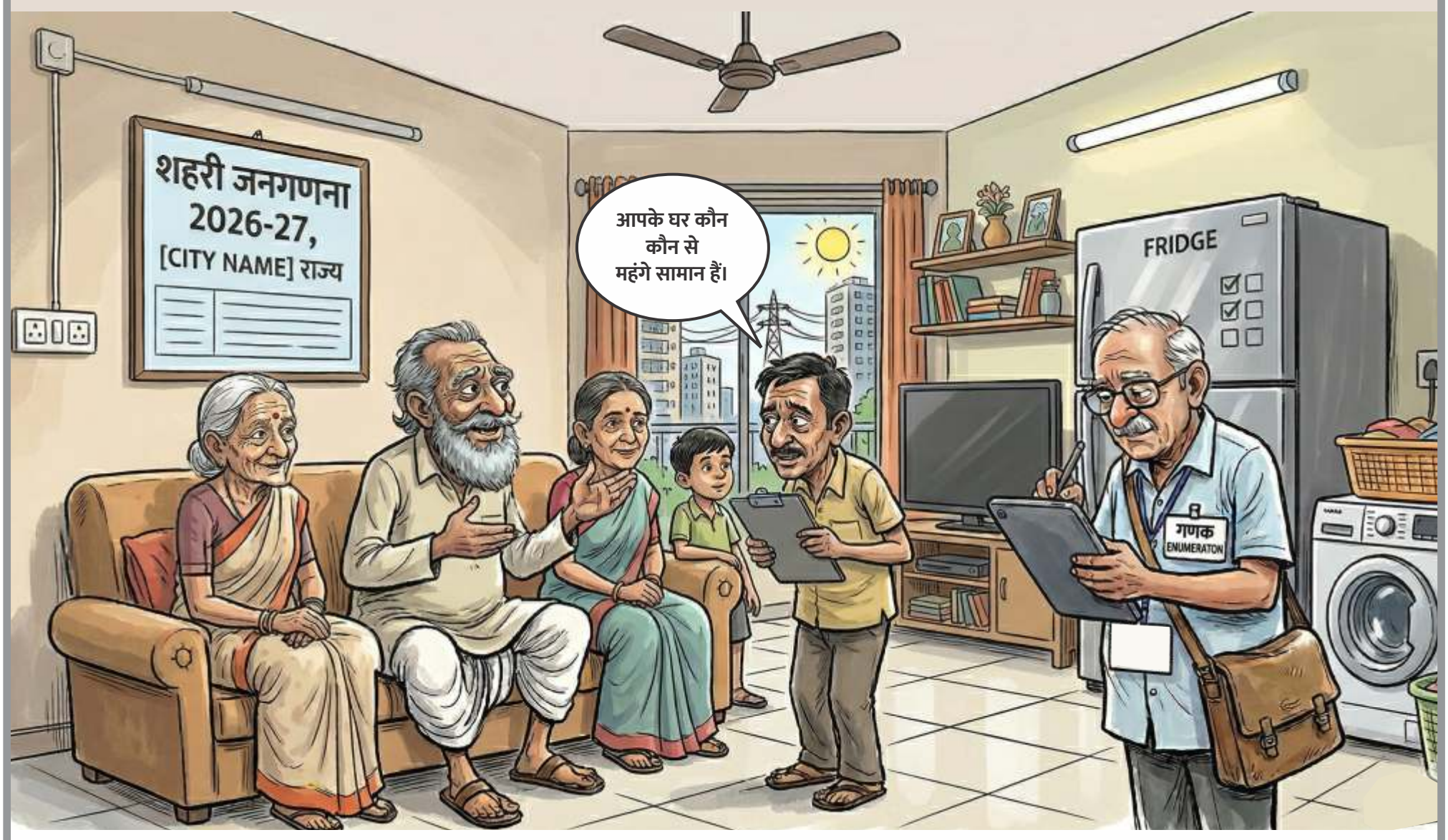

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

शहर सत्ता/रायपुर। जनगणना-2027 के पहले चरण में राज्य में 16 अप्रैल से मकानों की गिनती शुरू होगी। इस दौरान घर के सदस्यों की संख्या, मुखिया का नाम और मकान कच्चा है या पक्का, ये जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा घर में उपलब्ध बड़े सामानों का भी ब्योरा लिया जाएगा। इस बार की जनगणना में लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए 16 से 30 अप्रैल के बीच खुद ऑनलाइन फॉर्म भरने (स्व-गणना) का विकल्प दिया गया है। इस सुविधा से खासतौर पर उन परिवारों को राहत होगी, जो नौकरी या अन्य कारणों से दिन में घर पर नहीं रहते हैं।

एसआईआर सहित अन्य दूसरे सर्वे के दौरानअक्सर देखा गया है कि जब सर्वेयर टीम घर पहुंचती है तो वहां ताला लगा मिलता है। ऐसे में एक-दो बार कोशिश के बाद भी यदि कोई नहीं मिलता तो मकान को "डोर लॉक" मानकर एंट्री कर दी जाती है। इससे न तो सही पारिवारिक जानकारी दर्ज हो पाती है और न ही योजनाओं के लिए सही डेटा मिल पाता है।

अधिकारियों का कहना है कि इस स्थिति से बचने का सबसे आसान तरीका है खुद ऑनलाइन फॉर्म भरना। आनलाइन जनगणना के तहत के लिए सिर्फ 15 दिनों का विंडो खुला रहेगा। जनगणना का ऑनलाइन फार्म भरने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। स्व गणना पत्रक भरने के बाद एक 11 अंकों की एक आईडी मिलेगी। जब प्रगणक घर आएंगे तो उन्हें सिर्फ वो आईडी बतानी होगी। परिवार के सदस्य पड़ोसी या गार्ड को आईडी दे सकते हैं। वे सर्वेयर या प्रगणक टीम को आईडी दे सकते हैं। इससे जनगणना के डेटा सही और तथ्यात्मक रहेंगे।

जो जहां रहता है, उसी घर की देनी होगी जानकारी

जनगणना का पहला चरण मकानों की गिनती और वहां रहने वाले लोगों की जानकारी इकट्ठा करने से जुड़ा है। यदि एक व्यक्ति के एक से अधिक मकान हैं तो वह जिस मकान में रहता सिर्फ वहीं की जानकारी देनी होगी। बाकी के मकान किराये पर दिए गए हैं तो किरायेदार ही वहां की जानकारी देंगे। जनगणना निदेशालय के अफसरों के अनुसार इससे फर्क नहीं पड़ता कि मकान में मकान मालिक रह रहा है या किरायेदार। इसी तरह हास्टल में रहने वाले छात्र या छात्राएं भी जहां रहती हैं, वहां अपनी उपस्थिति दिखाते हुए वहीं की जानकारी देंगे।

इसलिए जरूरी है यह फॉर्म भरना

भविष्य की योजनाएं (पानी, सड़क, बिजली) की जरूरत का प्लान इसी डेटा से बनेगा {गलत/अधूरी जानकारी से क्षेत्र को कम संसाधन मिल सकते हैं, इससे समस्या बढ़ेगी {किरायेदार, बाहर रहने वालों के लिए उपयोगी।

अगर फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा

- घर बंद मिला "डोर लॉक" एंट्री
- पड़ोसियों से अधूरी जानकारी
- बाद में सुधार मुश्किल।

(असर: आपका सही डेटा सिस्टम में नहीं जाएगा)

1 मई से घर-घर दस्तक देंगे प्रगणक

30 अप्रैल तक स्वगणक प्रपत्रक भरने के बाद जनगणना निदेशालय के प्रगणक 1 मई से पूरे छत्तीसगढ़ में घर-घर पहुंचेंगे। जिन लोगों ने आनलाइन स्वगणना पत्रक भरें हैं, उनसे आईडी लेकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिन लोगों ने आनलाइन जनगणना पत्रक नहीं भरे हैं, उनसे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी लेकर पत्रक भरे जाएंगे। प्रदेशभर से 53 हजार प्रगणक जनगणना पत्रक भरने के लिए घर-घर पहुंचेंगे। पहले चरण की प्रक्रिया महीनेभर चलेगी।

ऑनलाइन स्वगणना समझें 5 आसान स्टेप में

1. **पोर्टल पर लॉगिन करें:** वेबसाइट खोलें: https://se.census.gov.in {अपना राज्य चुनें और कैप्चा भरें।
2. **परिवार का रजिस्ट्रेशन:** परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें {एक मोबाइल नंबर डालें (एक परिवार = एक नंबर) ओटीपी से वेरिफिकेशन करें
3. **लोकेशन मार्क करें** {जिला, गांव/शहर, पिनकोड भरें {मैप पर अपने घर का सही लोकेशन मार्क करें।
4. **फॉर्म भरें (मुख्य हिस्सा):** घर से जुड़े सवाल {मकान पक्का/कच्चा {पानी, शौचालय, बिजली {रसोई का ईंधन {इंटरनेट/मोबाइल उपलब्धता।
5. **सबमिट करें और एसई आईडी लें:** फॉर्म चेक करें {सबमिट करें {11 अंकों की एसई आईडी मिलेगी {इसे संभालकर रखें।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27